

हरियाणा विधान सभा की कार्यवाही

28 फरवरी, 2014

खण्ड-1, अंक-4

अधिकृत विवरण



विषय सूची

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2014

| | पृष्ठ संख्या |
|--|--------------|
| मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं संबंधी मामला उठाना | (4) 1 |
| वॉक आउट | (4) 2 |
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (4) 2 |
| एम0एल0एन0 महाविद्यालय, यमुनानगर के छात्रों/गुगल ब्याय, मास्टर कीटिल्य का अभिनंदन | (4) 3 |
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण) | (4) 4 |
| मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं संबंधी मामला उठाना/वॉक आउट | (4) 55 |
| अनुपस्थिति के संबंध में सूचना | (4) 58 |
| वर्ष 2014-15 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना | (4) 58 |

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

मुख्य मंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं संबंधी मामला उठाना

16.00 बजे श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Please take your seat. (Noise & Interruption) Vij ji, please take your seat.

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने 26.2.2014 को ही आपसे वायदा किया था कि ये किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे। (शोर एवं व्यवधान)
How can you speak like that Mr. Vij? You are such a senior Member of the House.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, * * *

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. Why are you shouting in the House? Why are you showing nice yourself? This is not the way. Please sit down. (Noise & Interruption) Listen to me. I am telling you to sit down please. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please take your seats. Please sit down. (Interruptions) आप प्लीज बैठ जाइये। Nothing is to be recorded. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हम व्यवस्था चाहते हैं। आज बजट पेश किया जाना है और उससे पहले कैबिनेट में फैसले किये जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Question hour will not be allowed to be disrupted. (Noise & Interruption) Mr. Ashok Arora, I am requesting you to resume your seat. Let the question hour go on please. (Noise & Interruption)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

वॉक-आउट

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker: Mr. Vjj, I am requesting you to sit down and this is the last request. Hon'ble Member, I will not request you any longer on. (Noise & Interruption) Please sit down. (Noise & Interruption) Please sit down. (Noise & Interruption) You cannot blackmail me like this. (Noise & Interruption) You cannot hold the Speaker to ransom. (Noise & Interruption) Hon'ble Member please resumes your seat. (Noise & Interruption) Please do not disturb the Proceedings of the House.

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker : Mr. Vjj, please don't disrupt the Proceedings of the House. (Noise & Interruption) Please sit down. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, हमें हमारी बात रखने का समय नहीं दिया जा रहा इसलिए हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य श्री अनिल विज को मुख्य मंत्री द्वारा सदन से बाहर मेजर अनाउंसमेंट किये जाने का मुद्दा न उठाने देने के कारण सदन से वॉक-आउट कर गये।)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the question Hour.

To Set up a Sugar Mill in Samalkha

***2011. Shri Dharam Singh Chhoker:** Will the Co-operation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Sugar Mill in Samalkha Assembly Constituency as the Panchayat of village Chhajpur is ready to provide the land for the purpose?

Cooperation Minister (Shri Sat Pal Sangwan) : No, Sir.

श्री धर्म सिंह चोकर : अध्यक्ष महोदय, पानीपत जिले का 80 प्रतिशत गन्ना समालखा विधान सभा क्षेत्र में होता है। उस क्षेत्र का गांव छाजपुर जो कि पानीपत छनौली रोड पर पड़ता है वहाँ की पंचायत चीनी मिल के लिए मुफ्त में जमीन देने के लिए तैयार है। अगर पानीपत की चीनी मिल जो कि शहर के कंजस्टिड एरिया के बीच में है, अगर उसको वहाँ से छाजपुर में शिफ्ट कर दिया जाये तो उससे किसानों को बहुत फायदा होगा और उनकी नजदीकता बढ़ेगी। इसलिए आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर चीनी मिल स्थापित की जाये।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने समालखा विधान सभा क्षेत्र के लिए जो चीनी मिल की माँग की है उसके बारे में मेरा कहना है कि हम पानीपत की चीनी मिल को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। उसी जगह पर उसमें कुछ टेक्नीकली और इकॉनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही हैं। इसमें तकरीबन 186 करोड़ रुपये लगेंगे जिसमें 10 प्रतिशत मिल को देने पड़ते हैं। दूसरा अब हम पानीपत के शुगर मिल की गन्ने की क्रसिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा रहे हैं। पहले इस शुगर मिल की गन्ने की क्रसिंग कैपेसिटी 18 हजार विन्टल थी जिसको अब बढ़ाकर 30 हजार विन्टल कर रहे हैं। मेरे भाई छोटकर साहब चाहे कितना ही गन्ना पैदा कर लें उनको क्रसिंग की प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। मैं यह बात हाउस के बीच में खड़ा होकर कहता हूँ। वैसे पहले भी हमने गन्ना बगैर क्रसिंग के नहीं छोड़ा है।

श्री जगवीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सोनीपत, गोहाना और जीन्द शुगर मिल की गन्ने की कितनी पेमेंट हो चुकी है और कितनी बकाया है और जो बकाया है उसकी पेमेंट कब तक हो जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : यह सैपरेट क्वेश्चन है इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है कि आज तक चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड़ा की सरकार में पिछले साल का किसी भी किसान का गन्ने का एक पैसा भी बकाया नहीं है। हमने गन्ने की सौ प्रतिशत क्रसिंग की है और सौ प्रतिशत उसकी पेमेंट कर दी है। मेरे माननीय सदस्य ने अब तक की गन्ने की पेमेंट की जो बात कही है मैं उनको बताना चाहूंगा कि अब तक जितना गन्ना हमने लिया है उसमें से तकरीबन 57 प्रतिशत तक सभी शुगर मिलों की गन्ने की पेमेंट कर दी है। इसके अलावा 50 करोड़ रुपये अभी पाइप लाइन में हैं यह राशि हम जल्दी देने जा रहे हैं। इस राशि को हमने प्लान बजट में भी रखा है। हमने किसान को गन्ने का बहुत बढ़िया रेट दिया है जिसके कारण किसान बहुत खुश हैं। मैंने हर शुगर मिल में विजिट किया है। (शोर एवं व्यवधान) **Speaker Sir, that is their habit, they cannot praise the thing.** हमारे विपक्ष के साथी यू.पी. का जिक्र कर रहे हैं कि यू.पी. में किसी किसान की गन्ने की पेमेंट बकाया नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ कि यू.पी. में आज भी किसानों की दो हजार करोड़ रुपये गन्ने की पेमेंट बकाया पड़ी है लेकिन हमारे हरियाणा में एक भी पैसा किसान का बकाया नहीं है। हमें घमण्ड है अपने मुख्यमंत्री जी पर कि आज एक भी पैसा किसान का बकाया नहीं है। हमारे ये साथी पिछले सरकार के समय का रिकॉर्ड निकाल कर देखे लें अब की सरकार का रिकॉर्ड देख लें कि पिछली सरकार में क्या था और अब क्या हो रहा है। स्पीकर सर, जैसे ही क्रसिंग का सीजन खत्म हो जाएगा हम किसानों की सौ प्रतिशत पेमेंट कर देंगे।

एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर के छात्रों/गुगल ब्याय, मास्टरकौटिल्य का अभिनन्दन

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हाउस को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एम.एल.एन. कॉलेज, यमुनानगर के छात्र आज दर्शक दीर्घा में इस सदन की कार्रवाही को देखने आए हैं। मैं इस सदन की ओर से उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कौटिल्य नाम का एक बच्चा जिसने अभी हाल ही में

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

हमारे हरियाणा का नाम पूरे देश में और बाहर के देशों में भी रोशन किया है, वह भी वी.आई.पी. गैलरी में मौजूद है। मैं सदन की ओर से उस बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ।

Mr. Speaker : We have honoured this boy separately in the Lobby today.

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भण)

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, पानीपत शुगर मिल जो हरियाणा का सबसे पुराना शुगर मिल है जिसकी क्रशिंग कैपेसिटी 18 हजार टन है और हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसकी क्रशिंग कैपेसिटी डबल करने की घोषणा की है और मंत्री जी इसकी कैपेसिटी 30 हजार टन बढ़ाने की बात कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस शुगर मिल की 36 हजार टन क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे यदि बढ़ाएंगे तो कितने समय में इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी

श्री सतपाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमें नाबाई से पैसे मिलने हैं। नाबाई को हमने सरकार की तरफ से इयोरटी भी दे दी है। हम पानीपत के शुगर मिल में 15 मैगावाट का जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। मैं यह बात ऐंग्री करता हूँ कि वह बहुत पुरानी मिल है उसकी कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं है। मेरे भाई पंवार साहब ने जो प्रश्न किया है मैं उनको इन्योर करता हूँ। हम इस शुगर मिल की जल्दी ही तकरीबन 186 करोड़ रुपये की लागत से 30 हजार टन क्रशिंग कैपेसिटी कर देंगे।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने इस शुगर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी डबल करने की घोषणा की है जिसकी दुगुनी क्रशिंग कैपेसिटी 36 हजार टन होनी चाहिए लेकिन मंत्री जी इसकी क्रशिंग कैपेसिटी केवल 30 हजार टन करने की बात कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको क्लीयर कर दें। स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में और मंत्री जी के जवाब में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मेरे पास मुख्यमंत्री जी की घोषणा की एक कटिंग भी है जिसमें बिल्कुल क्लीयर लिखा है कि पानीपत शुगर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी को डबल कर दिया जायेगा यानी जो क्रशिंग कैपेसिटी 18 हजार टन की है उस क्रशिंग कैपेसिटी को डबल करके 36 हजार टन कर दिया जायेगा जबकि मंत्री जी ने अपने जवाब में इस कैपेसिटी को 30 हजार टन की बजाय 30 हजार टन करने की बात कही है। अतः मंत्री जी इस बात को भलीभांति क्लीयर करें।

Mr. Speaker : Let the Hon'ble Minister reply.

श्री सतपाल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से भाननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यदि मुख्यमंत्री महोदय की इस प्रकार की कोई घोषणा है तो इसको भलीभांति वैरीफाई किया जायेगा परन्तु वर्तमान में तो हमारी पानीपत शुगर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी को 30 हजार टन करने का ही प्लॉन है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांगवान जी, प्लीज एक बार फिर से बतायें कि आपकी पानीपत शुगर मिल की क्रैशिंग कैपेसिटी को कितने टन करने की प्लॉन है?

श्री सतपाल : सर, हमारी पानीपत शुगर मिल की क्रैशिंग (crushing) कैपेसिटी को 30 हजार टन करने की प्लॉन है। (विष्ण)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, ... (विष्ण)

Mr. Speaker : Sangwan ji, it appears that Mr. Panwar is satisfied with the crushing capacity of 30 thousand tons also हां जी अरोड़ा जी अब आप अपनी बात रखिये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री धर्मसिंह छोकर जी ने समालखा विधान सभा क्षेत्र में शुगर मिल लगाने संबंधी प्रश्न किया है। अब जहां तक पानीपत में डबल शुगर मिल लगाने की बात आई है तो उस संबंध में मेरा यह कहना है कि जो पानीपत शुगर मिल है वह तकरीबन शहर के बीचों-बीच आ गई है जिसके कारण सड़क पर जाम रहने की समस्या एक आम बात हो गई है। मैं समझता हूँ कि यह प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने भी वहां से गुजरते हुए जरूर देखी होगी। इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जितना पैसा पानीपत में डबल शुगर मिल लगाने पर खर्च किया जायेगा, यदि इतना पैसा पानीपत शहर के बाहर शुगर मिल लगाने पर खर्च किया जाये तो कितना अच्छा रहेगा। अतः क्यों न इस मामले पर एक बार फिर से पुनर्विचार कर लिया जाये?

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, क्या आप मंत्री जी से केवल यही बात पूछना चाहते थे?

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : जी सर।

श्री सतपाल : स्पीकर सर, वैसे देखा जाये तो माननीय सदस्य श्री धर्म सिंह छोकर जी की जो प्रपोजल थी वह शुगर मिल को शहर से बाहर रखने के संबंध में ही थी। अब चूंकि अरोड़ा जी ने प्रश्न किया है तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अब पानीपत शुगर मिल का हर तरह से मॉडरेनाईजेशन किया जायेगा। जो मॉडर्नाइज्ड शुगर मिल होती हैं उनमें गैस अर्थात् गंदी बदबू आने की कोई समस्या ही नहीं रहती है। यदि माडर्नाइज्ड शुगर मिल के फायदे देखने हैं तो you can visit to Rohtak Modernized Sugar Mill. वहां पर गंदी बदबू आने की कोई समस्या नहीं है। जहां तक पंवार साहब ने पानीपत शुगर मिल की क्रैशिंग कैपेसिटी 30 हजार टन की बजाय 36 हजार टन करने की बात की है तो उस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस शुगर मिल की जो एक्सपेंडिड कैपेसिटी होगी वह 35 हजार टन की होगी और इसको आगे बढ़ाया भी जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। (विष्ण)

श्री धर्मसिंह छोकर : स्पीकर सर, पानीपत शुगर मिल की क्रैशिंग कैपेसिटी को 18 हजार टन से बढ़ाकर 30 हजार टन करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सहकारिता मंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा लेकिन इसके साथ ही मेरी यह भी प्रार्थना है कि यदि शुगर मिल को शहर के बाहर कर दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा जबकि यहां की पंचायत फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन देने के लिए तैयार भी है।

श्री अध्यक्ष : छोकर जी, मंत्री जी ने इससे संबंधित जवाब पहले ही दे दिया है अतः प्लीज अब आप बैठिये। (शोर एवं विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, देखिये. . .(विघ्न)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य छोकर जी तो सम्बंधित कार्य से खुश हैं लेकिन पंवार साहब बेवजह ही शोर कर रहे हैं। (विघ्न)

श्री कृष्ण लाल पंवार : स्पीकर सर, मेरा मकसद शोर करना नहीं है, मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि पानीपत शुगर मिल की क्रशिंग कैपेसिटी जोकि 18 हजार टन है, उसे बढ़ाकर डबल कर दिया जायेगा यानी यह क्रशिंग कैपेसिटी 36 हजार टन होनी चाहिए लेकिन मंत्री जी ने जो इस क्रशिंग कैपेसिटी को 30 हजार टन करने की बात की है वह सरासर गलत है। मैं तो मंत्री जी से केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी की घोषणा के मद्देनजर इस क्रशिंग कैपेसिटी को 6 हजार टन और बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : पंवार साहब, मंत्री जी इस संबंध में पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं अतः आप प्लीज बैठिये। Now, Mr. Tewatia Ji, you may please ask your question.

Construction of ROB

*2006. Shri Raghubir Singh Tewatia : Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that the foundation stone of Railway Over Bridge on Alawalpur railway crossing falling under the Prithla Assembly Constituency in District Palwal was laid down by the Hon'ble Chief Minister on 1-4-2012; if so, the time by which the work of the aforesaid railway over bridge is likely to be completed?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Yes sir. The work of construction of ROB at Palwal on Palwal-Alawalpur road crossing Delhi-Mathura Railway line (Level Crossing No. 566.) is in progress & is likely to be completed by 31-12-2014.

श्री रघुबीर सिंह तेवतिया : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सादर अनुरोध है कि अलावलपुर रेलवे फाटक पर रेलवे उपरिपुल बनाने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वह 18 महीने की थी लेकिन आज 23 महीने की अवधि बीत जाने के बाद भी इस पुल का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। यदि इस रेलवे उपरिपुल बनाने का कार्य जल्दी हो जाये तो 50 गाँवों के उन किसानों को इसका फायदा पहुँचेगा जिन्हें इस रास्ते से अपनी उपज लेकर पलवल अनाज मंडी में जाना पड़ता है। इसके साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में इस रेलवे उपरिपुल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, it is just a request. Please note down. Now, Mr. Nayyer, you may please ask your supplementary.

श्री जगदीश नायर : स्पीकर सर, मेरा प्रश्न भी तेवतिया जी के प्रश्न से ही लिंक करता है। होडल विधान सभा क्षेत्र में हसनपुर रेलवे फाटक पड़ता है। सन् 2011 में हसनपुर रेलवे फाटक पर

एक पुल बनना शुरू हुआ था लेकिन बाद में पुल बनाने का कार्य बंद हो गया। इस पुल के निर्माण कार्य पर रेलवे विभाग का भी काफी पैसा खर्च हो चुका है। मैंने इस रुके पड़े काम के बारे में जब अधिकारियों से बात की तो बताया गया कि इस कार्य के लिए हरियाणा सरकार से अभी पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है। स्पीकर सर, अब वर्तमान में तो ऐसे हालात हो गये हैं कि जो पुल का निर्माण कार्य था वह तो आलरेडी बंद हो ही गया है इसके साथ ही जो यहाँ पर फाटक बनाई जानी थी उसका निर्माण कार्य भी बंद हो चुका है जिसके कारण हमारे विधान सभा क्षेत्र के बाशिंदों को 10 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर गंतव्य तक पहुँचना पड़ता है। अलावलपुर में पुल बनाने का जो प्रोजेक्ट था, जोकि लगभग पूर्णता की अवस्था में है, वह हमारे हसनपुर रेलवे फाटक पर एक पुल बनाने वाले प्रोजेक्ट के काफी बाद आया था लेकिन हमारे पुल का काम वर्तमान में बंद पड़ा है। अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे इस पुल का कार्य क्यों बंद पड़ा है, इसका कारण बतायें?

Industries Minister (Sh. Randeep Singh Surjewala) : Sir, since it is a separate question. I agree with him that there must be an inconvenience. I will find out a solution. He should give it to me in writing, I will make sure that the work starts.

De-silting of Sewerage Lines

*2021. **Shri Anand Kaushik :** Will the Chief Minister be pleased to state—

- Whether it is a fact that the trunk sewerage lines and the trunk storm water lines have not been de-silted ever since these lines have been laid down in HUDA Sectors in Faridabad; and
- if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to de-silt the aforesaid sewerage and storm water lines before May, 2014?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : (a) No, Sir.

- De-silting of trunk storm water & sewerage lines in HUDA Sectors in Faridabad is being carried out as and when necessity arises.

श्री आनन्द कौशिक : अध्यक्ष महोदय, 35-40 साल पहले फरीदाबाद में हुडा द्वारा सैक्टर बनाये गये थे। इतना समय बीत जाने के बाद भी देखने में आया है कि हुडा प्रशासन द्वारा इन सैक्टरों से गाद नहीं निकाली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद के विकास में बहुत सारे विकास कार्य करवाये हैं और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया है। हुडा प्रशासन द्वारा सैक्टरों के रखरखाव की तरफ ध्यान न दिये जाने के कारण बरसात के सीजन में बारिश का पानी तीन-तीन दिन तक भी सड़कों पर खड़ा रहता है और इस प्रकार से सरकार द्वारा करवाये गये सारे विकास कार्यों पर पानी फिर जाता है। जिस तरह से किसान के लिए ड्रेनेज हैं का महत्व है उसके लिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इन ड्रेनेज की सफाई जून से पहले करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से एक और बात कहना चाहता हूँ कि ड्रेनेज की डिस्पोजल पर कम क्षमता वाली मोटरें लगी हुई हैं। इन पर बड़ी मोटरें लगाई जाये और

[श्री आनन्द कौशिक]

सीवरेज लाइज में दो महीने या तीन महीने बरसाती पानी चलता है। स्पीकर सर, विभाग को परमिशन दी जाये कि सीवर का पानी भी नहर में डाला जा सके क्योंकि बरसात के टाईम में सीवर की लाईन्ज में बरसात का पानी, स्टॉर्म वाटर खड़ा होने से सीवर लाइन ओवरफ्लो हो जाती है। मैं आपके माध्यम से मंत्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि यदि यह काम समय पर हो जाता है तो इससे लोगों को काफी राहत मिल सकेगी।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, you may give your suggestion in writing.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, there are two issues that my friend is raising. One is regarding cleaning of sewerage lines in HUDA sectors of Municipal Corporation, Faridabad. I want to point out him that HUDA undertakes regular cleaning of sewerage lines. In fact, in 2013-14, they have spent a sum of ₹ 21,79,58,000/-. However, I agree that if there is any further requirement left, we will take care of the same. On the demand of Shri Kaushik Ji, we have now also decided to purchase machines those he had written about. We have put it in the list of purchase on 14th January, 2014. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न उठाया है कि सीवरेज का पानी नहर में डालने के बारे में परमिशन दी जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि यह काम एनवार्यमेंट अथॉरिटी की परिधी में आता है। दिल्ली के चारों तरफ का सीवरेज का पानी बगैर ट्रीटमेंट के हालांकि दिल्ली के क्षेत्र में यमुना में डाला जाता है जबकि ऐसा करने पर पाबंदी है। फिर भी सीवरेज के पानी का डिस्पोजल किस प्रकार से हो सकता है, माननीय सदस्य इस बारे में मुझ से भी ज्यादा जानते हैं। इसलिए वे कुछ अपने सुझाव दें। उसके बाद इस पानी के डिस्पोजल के बारे में सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : कौशिक जी, इस बारे में आप राइटिंग में मंत्री जी को सुझाव दीजिए।

श्री आनन्द कौशिक : स्पीकर सर, मुझे विभाग से पता लगा है कि इस काम के लिए ऐस्टिमेंट बनाकर बण्डीगढ़ भेजा हुआ है। यदि विभाग द्वारा उस ऐस्टिमेंट को जल्दी से पास कर दिया जाये तो बरसात आने से पहले उस ड्रेनेज की सफाई हो सकती है तथा वहाँ के लोगों की समस्या का समाधान भी हो सकता है।

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, we will get it done.

Incentives for Mushroom Farming

*2017. *Shri Jai Tirath Dahiya: Will the Agriculture Minister be pleased to state—

- (a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to promote Mushroom Farming by giving the following incentives:—
- (i) The electricity connection on concessional rates as are being given to agriculture sector.

- (ii) The supply of Gypsum fertiliser on subsidised rates.
 - (iii) The insurance facility like other crops.
 - (iv) To declare Mushroom Farming as agricultural activity; and
- (b) If so, the details thereof together with the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialised?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : (a) Sir, the reply is as under :—

- (i) There is a provision for concession on electricity tariff for Mushroom activities on Agriculture feeders on which tariff is being charged at par with that of agriculture.
 - (ii) The proposal for supplying Gypsum fertiliser on subsidised rate is under consideration.
 - (iii) No, Sir.
 - (iv) Mushroom farming is Horticultural activity which comes under the agriculture sector.
- (b) In view of the reply to part (a) above, no exact time frame can be given at this stage.

Mr. Speaker : Mr. Minister, are you giving the electricity connections on concessional rates as are given for the Agriculture Sector?

Sardar Paramvir Singh : Sir, if they are on the agriculture feeders, they will be given the same facility.

Mr. Speaker : Yes, all these are locating in the agriculture sector. In fact, there are a lot of mushroom farms in my constituency. So, I just want to know whether the electricity connections to them are to be given on concessional rates as are given in the Agriculture Sector or not?

Sardar Paramvir Singh : Sir, if these are on agriculture feeders they will get the same subsidy.

Mr. Speaker : Mr. Minister, this question has arisen because either it is not being given the connections on concessional rates or it is not in the Agriculture Sector. There is something in it.

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I think the Minister is right. The concession can't be given on urban feeder. Concession has to be given on agriculture feeders only.

Mr. Speaker : All these are located in the agriculture sector.

श्री जगदीश सिंह मलिक : स्पीकर सर, जब चीप रेट पर किसानों को बिजली का कनेक्शन देते हैं तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ? स्पीकर सर, इसमें कनेक्शन की प्रायोरिटी पर देने की बात है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं समझता हूँ कि यह सवाल विद्युत मंत्री से पूछना चाहिए था न कि कृषि मंत्री से। मेरे माननीय साथी को इस बारे में विद्युत मंत्री को लिखकर देना चाहिए था ताकि इस मामले की जांच पड़ताल करवाई जा सके।

Sardar Paramvir Singh : Speaker Sir, we will write to Power Minister for clarification in this regard.

Mr. Speaker : Mr. Minister what is about gypsum and fertilizer subsidy?

Sardar Paramvir Singh : Sir, it is under consideration of the Government.

Mr. Speaker : Can you give a definite statement in this regard?

Sardar Paramvir Singh : Speaker Sir, it is under consideration of the Government and we will take a decision very soon.

Mr. Speaker : Mr. Minister are you going to declare Mushroom Farming as an agricultural activity?

Sardar Paramvir Singh : Sir that is horticultural activity and it comes under the agriculture sector.

Mr. Speaker : Are you declaring it on the floor of the House?

Sardar Paramvir Singh : Yes, Sir.

Abrupt Speed Breakers on Highways

*2018. **Shri B.B. Batra :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

- (a) Whether it is a fact that abrupt speed breakers have been erected on the National Highways as well as State Highways throughout the State;
- (b) Whether it is also a fact that no provision for any warning signals or blinkers have also not been made before the speed breakers; and
- (c) If so, the reason thereof togetherwith the time by which the aforesaid problem is likly to be solved by making provision of blinkers any warning signals?

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

For Part A) of the question

(i) Regarding construction of Speed Breakers on National Highways:

The Minister of Roads Transport & Highways, Government of India, vide its policy circular dated 28-06-1996 has emphasized that no speed breaker should be constructed on the National Highways and that only rumble strips are to be constructed where speed control is required. The circular also provides the specifications of rumble strips.

(ii) Regarding construction of speed Breakers on State Highways:

The Department of Public Works (B&R) vide memo dated 07-02-2011 has advised construction of speed breakers on the following locations as per IRC standards:

1. Junctions of National Highway (NH) with State Highway (SH)/ Major District Roads (MDR)/Other District Roads (ODR)
2. Junctions of SH with MDR/ODR.
3. Junctions of MDR with ODR.

(iii) However, it is a fact that several unauthorized speed breakers close to habitations, schools etc., have been erected on National Highways and State Highways. It is also a fact that most of these unauthorized speed breakers do not follow the laid specifications and are as a result, traffic hazard because of the abrupt angles of construction.

For B) & C) part of the question

Before authorized speed breakers, cautionary signal boards and markings are invariably provided besides strips and ceramic tiles on the breakers in linear format. However, for unauthorized speed breakers, the same cannot be provided/ensured. Blinkers/warning lights can be provided in urban areas by the Urban Local Bodies. NHAI provides blinkers/directional lights, wherever required too. The public needs to be educated about the hazardous speed breakers, while the driving skills and sensitivity for the safety of the pedestrians also need to be inculcated amongst the drivers.

The matter has been reviewed by the State Road Safety Council under the Chairmanship of Hon'ble Transport Minister and as per its directions a State wide campaign for marking signage, road painting and educating the public about these issues was launched during 14th January to 19th January, 2014. The Government of Haryana and NHAI have successfully removed 112 speed breakers out of the 160 unauthorized speed breakers on National Highways in the last three months. The Deputy Commissioners have been issued instructions to ensure that

[Shri Randeep Singh Surjewala]

no unauthorized speed breakers are erected on National Highways and to speedily take action to remove these already erected.

श्री भारत भूषण बतसरा : स्पीकर सर, जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है उसमें तो वही लीगल प्रिविलेज दिये गए हैं। राज्य में बहुत सारे स्पीड ब्रेकर अनऑथराइज्ड हैं। Why PW Department is not reviewing these speed breakers? दूसरा सवाल यह है कि जो स्पीड ब्रेकर अनऑथराइज्ड भी हैं उनके बारे में भी इन्होंने लिख दिया कि इस बारे में नेशनल हाईवे अथोरिटी में इन्सट्रक्शंस हैं। स्पीकर सर, राज्य के अंदर किसी भी जगह जहां स्पीड ब्रेकर हैं उनसे पहले वार्निंग साइन्ज एण्ड बिलंकर्स दिखाए जाएं या कोई फोटो साइन दिखाया जाए। मंत्री जी कहते हैं कि राज्य में टोटल 160 अनऑथराइज्ड स्पीड ब्रेकर हैं जिनमें से 112 हमने रिमूव कर दिये हैं। स्पीकर सर, यह बात ठीक है कि ये स्पीड ब्रेकर आकस्मिक दुर्घटना की रोकथाम के लिए होते हैं लेकिन अधिकतर दुर्घटनाएं इन्हीं स्पीड ब्रेकर के कारण से होती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा कि क्यों नहीं हम इन ब्रेकर से पहले वार्निंग साइन्ज एण्ड बिलंकर्स लगा दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय काबिल साथी की चिंता जायज है। हमने नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर एम.डी.आर. और ओ.डी.आर. के जेक्शन हैं उन पर भी हमने स्पीड ब्रेकर लगाए हैं। माननीय सदस्य का प्रश्न आने के बाद सरकार ने एक डिटेल्ड सर्वे करवाया था, जिसमें यह पाया गया कि जो 497 स्पीड ब्रेकर जो राज्य के 875 राजमार्गों पर हैं वे स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया के मुताबिक सही हैं फिर भी जैसाकि माननीय सदस्य ने धिंता जाहिर की है वार्निंग साइन्ज एण्ड बिलंकर्स लगाने के लिए हम इस बारे में हिदायतें जारी कर देंगे। 378 स्पीड ब्रेकर ऐसे हैं जो सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। कई बार पुलिस फोर्स के साथ ऐसे स्पीड ब्रेकर रिमूव भी करवा दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप और हम ग्रामीण आंचल से आते हैं। हम सब यह देखते हैं कि उसके बावजूद भी स्थानीय ग्रामीणों की भागों के चलते उसमें चाहे स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि पंचायत के सरपंच साहेबान हों, चाहे नगरपालिका के साथी हों या चाहे दूसरे कोई साथी हों उनके द्वारा फिर बना लिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि इन स्पीड ब्रेकर से पहले वार्निंग साइन्ज एण्ड बिलंकर्स लगवा दिए जायेंगे।

श्री भारत भूषण बतसरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी अनऑथराइज्ड स्पीड ब्रेकर के बारे में लोगों को सावधान करने के लिए कोई टाइम फ्रेम करेंगे ? I am not talking about the unauthorized speed breakers मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार का कोई साइन बोर्ड लगाएंगे कि "आगे गति अवरोधक है, धन्यवाद" या साथ में बिलंकर्स वगैरह लगवाएंगे और यदि लगवाएंगे तो ये कितने समय में लग जाएंगे, यह भी जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट फ्रेम करेंगे ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, I agree with my Learned friend. We will try and do it over within next three months.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया है कि कुल 300 अनअथोराइज्ड स्पीड ब्रेकर्स हैं, कुछ अथोराइज्ड भी हैं क्या उनकी जिलेवाइज संख्या बताएंगे कि कहां कहां पर कितने-कितने स्पीड ब्रेकर्स हैं ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, यह इन्फर्मेशन मेरे पास रेडीली अवेलेबल नहीं है। मैं यह इन्फर्मेशन मेरे बड़े भाई श्री अशोक अरोड़ा साहब के पास भिजवा दूंगा।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही अच्छा प्रश्न आदरणीय बत्तरा साहब ने उठाया है। वैसे काफी सारी सड़कों पर इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं लेकिन मैं नेशनल हाइवे नंबर-1 के बारे में कहना चाहूंगा क्योंकि वहां पर काम होते होते रुक गया और बहुत सारे डायवर्शन बने हुए हैं और वहां पर कहीं साइन नहीं बने हुए हैं। अम्बाला से दिल्ली तक के हाइवे के बारे में तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वहां एक भी केजरीवाल साइन नहीं लगाया गया है। (केजरीवाल साइन यानी यू टर्न) (हंसी) सर, आजकल यू टर्न को केजरीवाल साइन ही कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से चला गया तो काफी आगे जाकर मुड़कर वापस आना पड़ता है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह साइन लगवाए जाएंगे ? Sir, I am serious about it.

Mr. Speaker : Vij ji, you are not serious. Only answer is given to the serious questions.

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गुड़गांव से अलवर वाया सोहना-नूंह-फिरोजपुर झिरका के लिए जो रास्ता जा रहा है, वह राज्य राजमार्ग हैं। गुड़गांव से फिरोजपुर झिरका की दूरी 84 किलोमीटर है उसके दरमियान 90 स्पीड ब्रेकर्स हैं क्या वहां पर स्पीड ब्रेकर्स रम्बल स्ट्रिप्स टाइप में बनाए जाएंगे या उनको वहां से हटाया जाएगा। हमारे मेधात एरिया में पहाड़ राजस्थान से ही चल रहा है और पत्थरों से भरे हुए डम्पर चलते हैं उनकी वजह से बहुत हादसे होते हैं वहां न कोई सिग्नल है, न कोई निशानी है। क्या उन रोड्स के लिए सरकार इस बारे में कोई प्रावधान करेगी ?

Shri Randeep Singh Surjewala : Sir, we make sure that unauthorized speed breakers will be removed. बाकी जो अथोराइज्ड ब्रेकर्स हैं उन को भी हम प्रोपर वे में बनवाएंगे।

प्रो.संपत सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोड सेफ्टी के लिए स्पीड ब्रेकर का प्रोपर वे और प्रोपर प्लेस पर होना बहुत ही जरूरी है और आज के दिन स्पीड ब्रेकर न ही प्रोपर प्लेस पर हैं न ही प्रोपर वे में बने हुए हैं। ट्रक में रोड़ी, बजरी, ईट पत्थर डालकर ले आते हैं और स्पीड ब्रेकर बना लेते हैं। जो अनअथोराइज्ड स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं वह तो ऐक्सीडेंट होने की वजह से लोगों की मांग पर बना दिये जाते हैं उसके लिए तो अध्यक्ष महोदय आप और हम भी कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर बना दो। लेकिन बाकी के जो स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं वह तो एकदम से देही तोड़ और गाड़ी तोड़ बने हुए हैं। अभी जो खदान में विज साहब ने यू टर्न की परिभाषा दी है वह तो संभवतः विज साहब पर श्वयं पर धी लागू होती है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे यू टर्न लिए हुए हैं। उनके लिए ये नाम लेने की बात ही तो अच्छा हो जाएगी। (हंसी)

Grain Market at Matlauda

***1818. Sbri Naresh Seifwal :** Will the Agriculture Minister be pleased to state the time by which the new Grain Market in Matlauda is likely to be started ?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh) : Sir, no new Grain Market in Matlauda has been envisaged.

श्री नरेश सेलवाल : स्पीकर सर, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है और इसके बारे में फाइल विभाग से आई हुई है और दो महकमे होने के कारण यह मामला अटका हुआ है क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड 5 प्रतिशत पैसा देना चाहता है जबकि पंचायती राज दस प्रतिशत पैसे की मांग कर रहा है। फाइल विभाग से आई हुई है क्योंकि मैं फाइल की मुवमेंट पर नजर रखे हुए हूँ। विभाग के अधिकारियों ने जो भी रिपोर्ट मंत्री जी को दी है वह गलत रिपोर्ट दी है। यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल है इसलिए मंत्री जी इस पर ज्यादा ध्यान दें। यही मेरा मंत्री जी से अनुरोध है।

Sardar Paramvir Singh : Speaker Sir, this matter has been reviewed and the same has been dropped.

Technical Modernization and up-gradation of Sugar Mill

***1981. Smt. Sumita Singh :** Will the Cooperation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the technical modernization and upgradation of the Karnal Comperative Sugar Mill?

Cooperation Minister (Shri Satpal) : Yes, Sir.

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि करनाल की शुगर मिल का कब तक मॉडर्नाइजेशन कर दिया जायेगा? माननीय मंत्री जी इस बारे में काफी सीरियस हैं। मैं जब भी उनसे मिलती हूँ तो वह यही कहते हैं कि मैं इस काम को कर रहा हूँ लेकिन इस बात को कहते हुए कई साल हो गये हैं।

श्री सतपाल : स्पीकर सर, माननीया सदस्या को इस बारे में पहली दफा सदन में क्वेश्चन किया है। She has never been told me about this report till today. माननीया सदस्या को ऐसा नहीं बोलना चाहिए।

श्रीमती सुमिता सिंह : स्पीकर सर, मैं यह तो भानती हूँ कि माननीय मंत्री जी काफी समय से करनाल की शुगर मिल का मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं और यह बाल कई दिनों से चल रही है। माननीय मंत्री जी इस बारे में सीरियस भी हैं और ये इस काम को करना भी चाहते हैं। करनाल की शुगर मिल हमेशा ही हरियाणा राज्य में प्रथम आती है और कई बार इस शुगर मिल को ईनाम भी मिला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या बजट में इस बारे में कोई प्रोविजन किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, माननीय सदस्या यह पूछ रही हैं कि क्या आपने इस काम के लिए बजट में कोई प्रोविजन रखा है या नहीं ?

श्री सतपाल : स्पीकर सर, करनाल शुगर मिल पर 90 करोड़ रुपया खर्च किये जायेंगे और इस शुगर मिल की 22 हजार से 25 हजार क्विंटल गन्ने की पिराई की कैपेसिटी भी बढ़ाई गई है। 90 करोड़ रुपये का डिटेल्ड प्रोजेक्ट नाबार्ड से तैयार हो गया है। इसके लिए डी.एन.आई.टी. (Detailed Notice Inviting Tender) तैयार हो गई है और नेशनल फेडरेशन, दिल्ली से पास कराना था वह पास भी हो गया है और अब लास्ट टाइम नाबार्ड से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग कर ली है। अब हम इसको जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। जहां तक प्राइज का सवाल है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिसकी तीन शुगर मिलों को प्राइज मिला था और कोई ऐसा प्रदेश नहीं था जिसको इतने प्राइज मिले हों। शाहबाद मारकण्डा शुगर मिल, पानीपत शुगर मिल और करनाल शुगर मिल इन तीनों मिलों को प्राइज मिला था जोकि एक रिकार्ड है। उत्तर प्रदेश की एक शुगर मिल को प्राइज मिला था और महाराष्ट्र जिसके कि केन्द्रीय मंत्री हैं वहां की एक भी शुगर मिल को प्राइज नहीं मिला और जिस गुजरात की विज साहब बात कर रहे हैं उसका तो कहीं जिद्द ही नहीं है।

Dilapidated Condition of CHC, Hassanpur

*1826. Shri Jagdish Nayar: Will the Health Minister be pleased to state---

- Whether it is a fact that the building of CHC Hassanpur, District Patwal is in dilapidated condition;
- Whether it is also a fact that required medical staff has not been provided in this CHC; and
- If so, the time by which the repair of building, as at (a) above is likely to be done and the required staff, as at (b) above, is likely to be provided?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

(ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हसनपुर के लिए स्वीकृत अधिकतर अमला प्रदान कर दिया गया है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनपुर के लिए अतिरिक्त अमला स्वीकृत करना सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के जवाब में नहीं श्रीमान जी कहा है। अध्यक्ष महोदय, हमारे हसनपुर की पी.एच.सी. की बिल्डिंग की हालत काफी खस्ता है जिससे भरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहां डाक्टरों के निवास टूटे पड़े हैं और स्टाफ की भी भारी कमी है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का समय पूरा होने जा रहा है इसलिए अब तो सरकार बता दे कि कितनी राशि उस पी.एच.सी. के लिए अलॉट की गई है तथा वहां स्टाफ की कमी को कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिल्डिंग का सवाल है तो वर्ष 1984 से सरकारी भवन में हसनपुर की पी.एच.सी. काम कर रही है। वर्ष 2012-13 में इसकी रिपेयर पर 3 लाख 61 हजार 848 रुपये खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 2009 में उनकी पी.एच.सी. को अपग्रेड करके सी.एच.सी. बनाया गया है। जहां तक स्टाफ की बात है या क्वार्टर बनाने की बात है तो वह अभी विचाराधीन है। मैं समझता हूँ कि कमिंग फाइनेंशियल इयर में हम क्वार्टर बना देंगे और स्टाफ की कमी को पूरा कर देंगे।

श्री जगदीश नायर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे बंटवारे में केवल 3 लाख रुपये ही आए हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने होडल में 100 बेड का होस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। मेरे हिसाब से अब वहां केवल 10 बेड भी पूरे नहीं आ सकते इसलिए केवल घोषणाएं ही हो रही हैं काम नहीं हो रहे हैं।

राव नरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनके हल्के में सी.एच.सी. बनाने की बात कही गई है और सी.एच.सी. के लिए जितनी बिल्डिंग पर्याप्त होगी चाहिए वह हम कमिंग फाइनेंशियल इयर में बना देंगे और जितना स्टाफ सी.एच.सी. के लिए चाहिए वह हम कमिंग फाइनेंशियल इयर में पूरा कर देंगे।

Regular Drinking Water Supply

***1839. Shri Kali Ram Patwari :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state—

- Whether it is a fact that there is no proper and adequate drinking water supply in villages, such as Ludana, Malseri Khera, Morkhi, Gangoli, Bharatana, Dharoli, Mandi Mohammad Khera, Aalan, Jogi Khera, Muana, Singhana etc. in Safidon Constituency; and
- If so, time by which regular and proper drinking water supply is likely to be provided in these villages?

Public Health Engineer Minister (Smt. Kiran Choudhary) :

- No Sir.
- Needs no reply in view of (a) above.

श्री कलौराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी सफ़ीदों कांस्टीच्युंसी में लुदाना, मलसरी खेड़ा, मोरखी, गंगोली, भरताना, धरौली, मण्डी, मोहम्मद खेड़ा, आलान, जोगी खेड़ा, मुआना, सिंघाणा आदि गांवों की बाहर वाली नई आबादी में तो पानी की सप्लाई है परंतु इन गांवों के बीच की जो ऊंची आबादी है वहां कहीं भी पानी की सप्लाई नहीं पहुंच रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इन गांवों के बीच वाली आबादी में पानी की सप्लाई पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और यदि की जाएगी तो कब तक की जाएगी ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इनकी कांस्टीच्युंसी में 22 गांव हैं और पूरे 22 गांवों के अंदर 40 एल.पी.सी.डी. तक पानी उपलब्ध है यानी पानी की कोई कमी नहीं है इसलिए इनको इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये चाहेंगे तो मैं गांव वाइज डिटेल भी बता दूंगी।

श्री कलीराम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछा है कि क्या गांव के बीच वाली आबादी में पानी पहुंचाने का काम करेंगे या नहीं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको गांव वाइज डिटेल ही बता देती हूँ- लुदाना में 55 एल.पी.सी.डी. पानी है यानी मिनीमम से ज्यादा है। वहां पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक शैलो ट्यूबवैल इन्स्टाल कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, ये जानते हैं कि 40 एल.पी.सी.डी. पानी हम मिनीमम रख रहे हैं। मलसेरी खेड़ा में 55 एल.पी.सी.डी. पानी है और वहां कैनाल बेस्ड पानी दे रहे हैं। मोरखी के अंदर कैनाल बेस्ड 45 एल.पी.सी.डी. पानी है। अध्यक्ष महोदय, इनको जानकर खुशी होगी कि एक नया ट्यूबवैल 18.35 लाख रुपये की कोस्ट से प्रोग्रेस में है और वहां से भी इनके यहां पानी जल्द आ जाएगा।

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछा है कि हमारे इन गांवों में बाहर की आबादी में तो पानी पहुंच रहा है लेकिन गांवों के बीच की आबादी में पानी नहीं पहुंच रहा है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं गांवों की बाल कर रही हूँ जिन गांवों का इन्होंने लिखकर भेजा है। (विघ्न)

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि गांवों के बीच की आबादी में पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिए वहां कब तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे।

Mr. Speaker : Hon'ble Member, let the Minister complete her reply.

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रही हैं।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मेरी इनसे प्रार्थना है कि ये मेरी पूरी बात सुन लें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि इनके हल्के के मोरखी गांव के अंदर 18.35 लाख रुपये की लागत से ट्यूबवैल लगाया जा रहा है जो कि अगले महीने 31.3.2014 तक बन जायेगा।

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही कि जो गांव के बीच में ऊंचाई का एरिया है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि मोरखी का ट्यूबवैल 31.3.2014 तक बन जायेगा यह आश्वासन मैं on the floor of the House दे रही हूँ। इसी तरह से गंगौली के अंदर एक नया ट्यूबवैल वाटर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लगाया गया है जबकि पहले ही वहां पर 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है। इसी तरह से बरताना गांव में भी 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है, वहां भी एक नया ट्यूबवैल लगाया गया है। इसी तरह से घड़ोली के अंदर भी एक नया डीप ट्यूबवैल at the cost of Rs.25.55 lac is in progress

[श्रीमती किरण चौधरी]

और वह 31.3.2014 तक बनकर तैयार हो जायेगा जबकि वहां भी 55 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा रहा है। इसके लिए माननीय साथी को मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए।

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा सा सवाल यह है कि मेरे हल्के के अंदर गांवों के अंदर बीच में जो आबादी ऊंचाई पर रहती है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? ट्यूबवैल्वज जो लगाये जा रहे हैं इसकी जानकारी तो मुझे है लेकिन ऊंचाई पर जिन एरियाज में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा वहां पर पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी है ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो ऊंचाई या नीचाई की बात है इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री कली राम पटवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जहां ऊंचाई के एरियाज में पानी नहीं पहुंच रहा वहां पर पानी कौन पहुंचाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पानी तो हम ही पहुंचाएंगे लेकिन माननीय साथी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं हैं। माननीय सदस्य के हल्के में 14 नई स्कीमज पर 380.10 लाख रुपये की लागत से काम चल रहा है ताकि वहां पर लोगों को 40 से 55 और 70 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रति दिन दिया जा सके। इसके लिए माननीय साथी को मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। यह बहुत दुख की बात है। माननीय सदस्य सरकार का धन्यवाद करने की बजाय इधर-उधर की बात करके उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे को ये लोग उलझा नहीं सकते हैं क्योंकि मुझे अपना जवाब देना आता है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे माननीय साथी ने ऊंचाई में रहने वाले लोगों तक पानी पहुंचाने के बारे में सवाल किया है और इस तरह की समस्या तकरीबन पूरे प्रदेश में बनी हुई है। (विध्न)

श्री अध्यक्ष : यह एक बड़ी सिम्पल सी प्रोब्लम है। Hon'ble Minister this problem is generally being discussed. (interruption)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कली राम जी मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे। इनके हल्के में करोड़ों रुपये लगाकर ट्यूबवैल्वज लगाये जा रहे हैं इसका मतलब यही है कि जिन एरियाज में पानी नहीं पहुंच रहा उनमें भी पानी जायेगा। It is very simple. I don't think this. There is no rocket science in this. इसमें कोई रॉकेट साईंस वाली बात नहीं है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में जहां ऊंचाई के एरियाज में पानी नहीं पहुंच रहा क्या उन एरियाज में ओ.एच.एस.आर. या बूस्टिंग स्टेशन लगाकर पानी पहुंचाया जायेगा। स्पीकर सर, दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर न तो मंत्री महोदय का महकमा जिम्मेवारी उठाला है और न ही पंचायती राज महकमा जिम्मेवारी उठाला है। आज प्रदेश में पब्लिक हेल्थ विभाग ने बड़े-बड़े गांवों में यह समस्या क्रियेट कर दी कि जिन गांवों में तालाब गांव के बीच में आ गये हैं वे ओवर फ्लो रहते हैं। इसका मेन

कारण यह है कि गांव के नीचले इलाकों में पानी की टूटी पूरे टाइम चलती रहती हैं जिसके कारण रिहायशी इलाकों में भी पानी भर जाता है। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक पानी पहुंचाने के बारे में सवाल पूछा है इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हम हर जगह पानी दे रहे हैं और बड़े सिस्टमैटिकली यह कार्य चल रहा है। फिर भी जिन एरियाज में पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर पानी पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। जहां तक माननीय सदस्य ने टूटियां खुली होने के कारण पानी भरने की बात की है इस बारे में माननीय सदस्य नाम बतायें कि कहां पर ऐसा हो रहा है। मैं माननीय सदस्य से यह भी कहना चाहूंगी कि being a responsible citizen इनको भी लोगों में अवैयरनेस फैलानी चाहिए कि इस तरह से लोग टूटियां खुली न रखें क्योंकि पानी बहुत कीमती है और एक-एक बूंद पानी बचाना हमारी जिम्मेवारी है।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो सीधा सा सवाल मंत्री जी से यही था कि जहां पर वाटर ओवरफ्लो हो रहा है और रिहायशी इलाकों में जाता है उसको रोकने के लिए सरकार कोई स्कीम बनायेगी तथा दूसरा सवाल यह था कि जहां ऊंचाई के एरियाज में पानी नहीं पहुंच रहा है वहां पर ओ.एच.एस.आर. या बूस्टिंग स्टेशन लगाकर पानी पहुंचाने का कार्य किया जायेगा।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि जहां पर जरूरत है वहां पर बूस्टिंग स्टेशन लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आने वाली 3 तारीख को हमारे क्षेत्रीय बोर्ड की मीटिंग होनी है जिसमें और कहीं भी बूस्टिंग स्टेशन लगाने की जरूरत होगी तो उसके लिए भी पैसा निर्धारित किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जहां तक ओवरफ्लो की बात कही है इसका मतलब यह है कि वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। (विघ्न)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसे कारगर कदम उठाये जिससे पानी की वेस्टेज रूके और साथ ही साथ जरूरत के इलाकों में भी पानी पहुंच सके।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, आज मैं यहां पर सदन के अंदर एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहूंगी कि पानी जो है it is a very limited resource and one of the most important resources for livelihood and also for our lives. Everybody must make it a kind of awareness programme that we have to save water because just pointing out figures on the Government will not work. This has to be done in terms with the people otherwise just the Government cannot do something like this. People have to be told in this regard and elected Members of this august House are also equally responsible for bringing this awareness to the people.

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। सरकार की तरफ से गांव-गांव में पीने का साफ व स्वच्छ पानी पहुंचाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी गई है लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है सारी की सारी कमी उसी में है। जिस प्रकार से सरकारी विभाग की तरफ से पानी की सप्लाई का सिस्टम बनाया गया है जिसमें 10 से 20 घंटे के लिए एक स्टैंड-पोस्ट लगाया जाता है उसके अलावा भी लोग अनधिकृत और असुरक्षित तरीके से जगह-

[श्री आनंद सिंह दांगी]

जगह पर उस पानी की मेन पाइप लाइन को तोड़कर अपना-अपना कनेक्शन लगा लेते हैं। जहां से वे पानी की मेन पाइप लाइन से अपना पानी का कनेक्शन लेने के लिए पाईप जोड़ते हैं उसको ठीक ढंग से बंद नहीं करते जिस कारण जोहड़ो व नालियों का गंदा पानी भी उस पानी की मेन पाइप लाइन में चला जाता है। जब हम गांवों में जाते हैं तो लोग बोतलों में भरकर हमें दिखाते हैं कि देखिए हमारे यहाँ पीने का गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसमें एक सत्य बात यह भी है जैसा कि रामपाल माजरा जी ने कहा कि लगभग सभी गांवों के जोहड़ भर चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सही एक कारण है कि ये जो टैप्स लगाये जाते हैं उनको पब्लिक तोड़ देती है और उसके बाद वे खुले चलते रहते हैं। इसके साथ-साथ इसका एक कारण यह भी है कि पब्लिक हेल्थ के ट्यूबवैल्व को चलाने के समय का भी कोई सिस्टम नहीं है वे ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलाये जाते बल्कि लगातार दिन-रात चलते रहते हैं। जो यह पानी की मेन पाइप लाइन पंक्चर की जाती है अगर इस कमी को दूर कर दिया जाये तो फिर हमारे गांवों, कस्बों व शहरों की ऊंचे और नीचे क्षेत्रों में रहने वाली समस्त जनता को पीने का साफ व स्वच्छ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, दांगी साहब ने यह एक बहुत अच्छी बात बताई है। मैं यहाँ पर यह बताना चाहूंगी कि ऐसे मामले में ज्यादातर यह होता है कि जो हमारी वॉटर पाईप लाईन हैं उसमें लोग अपने प्राइवेट कनेक्शन जोड़ लेते हैं। यह दांगी साहब ने सत्य कहा है। ये जो प्राइवेट कनेक्शन लिये जाते हैं इनके जो पाईप होते हैं these are not of a good quality because पैसा बचाने के लिए या फिर दूसरे कारणों से वे लोग ये घटिया क्वालिटी के पाईप डाल देते हैं Result is this once the pipe line becomes bad और वह जर्जर हालत में हो जाती है जिस कारण वही पानी जहाँ से ऐसे लोगों द्वारा कनेक्शन लिया जाता है that same water becomes contaminated and comes into the main line. Sir, once this water comes into the main line then naturally it comes into all these bottles as Mr. Dangi Ji told. The fact of the matter is that we have asked our department and we have made this awareness all over the State as well as in every city कि वे लोग जिनकी पाईप लाईन पुरानी हैं वे उसे बदल लें और अगर वे खुद उसे नहीं बदल सकते then our department is willing to help them to do it but unfortunately nobody is willing because you see that they have to pay money out of their own pockets for this purpose and they are not prepared to do that. Speaker Sir, Government cannot do each and everything. We can only bring the main pipeline and we cannot bring the pipe line to anybody's house because that has to be done by the person concerned. Sir, as far as, Mr. Dangi's request for taking water at higher level places is concerned I want to submit that in many places in the State we have already done it. We are also in the process of doing it, that boosting stations are being made for which we are acquiring land so that through these boosting stations we can pump water to these areas where water is not available.

श्री आनंद सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह बात मानता हूँ कि जहाँ पर बूस्टिंग स्टेशनों की ज़रूरत है वहाँ पर बूस्टिंग स्टेशन बनने लग रहे हैं और जहाँ-जहाँ वॉटर वर्क्स की ज़रूरत है वहाँ-वहाँ वॉटर वर्क्स भी बने हुए हैं लेकिन मैं फिर से यह बात दोहराना चाहता हूँ कि

जो पानी की सप्लाई का सिस्टम है लोग उससे छेड़खानी करके उसको बिगाड़ रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि जो लोग अपने आप पाईप लगाते हैं उनकी क्वालिटी खराब है। मैं यह कह रहा हूँ कि जो पानी की मेन पाईप लाईन है लोगों ने उसको खराब कर दिया है। इसी कारण से सारी की सारी समस्याएँ पैदा होती हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए कोई प्रॉपर चैकिंग का सिस्टम बनाये ताकि इस तरह से लोग पानी की मेन पाईप लाईन को डैमेज न करें। जितनी वाटर स्टैंड रिक्वायरड हैं उतने ही लगाये जाने चाहिए और किसी को भी पानी की मेन पाईप लाईन अपने आप तोड़कर प्राइवेट पाईप लगाने की परमिशन न हो। इसी के कारण पानी खराब भी हो जाता है, वेस्ट भी बहता रहता है और इस प्रकार की सारी की सारी शिकायतें चाहे ऊंची आबादी के पास पानी पहुंचाने की बात है या फिर गंदे पानी की सप्लाई की बात हो वे सभी इसी के कारण हैं। कहीं पर तो लोग अपने पशुओं को नहला रहे होते हैं और कहीं पर लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं पहुंचता। सिस्टम में सारी खराबी यह है। अगर माननीय मंत्री महोदय इसका सुधार कर दें तो लगभग सभी समस्याएँ अपने आप हल हो जाएंगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दांगी साहब को एक बात बताना चाहती हूँ कि पहले पानी की मेन पाइप लाईन में सीमेंट की पाईप डाली जाती थी लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब लोहे की पाईप डाली जाएंगी। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि जो मेन पाईप लाईन्स हैं उनके अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। जो मैंने बताया है कमी उस तरीके की है। एक बात इन्होंने दोबारा से कही है कि हाई लेवल के इलाकों में पानी नहीं जाता वहां we are in the process कि जहां-जहां हमारे पास आता है we take care of that whole thing for which we are making boosting stations to the tune of crore and crores of rupees therefore, Hon'ble Members should be thankful the way the Public Health Engineering Department is working.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष जी, मैं भी इस विषय के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

Mr. Speaker : Sampat Singh Ji, enough supplementaries are made on this question. This question is going on for the last 9 minutes. (Interruption) ठीक है सम्पत सिंह जी आप बोलिए but this is the last supplementary.

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में भी मैंने प्रश्न पूछा था कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हाउसहोल्ड के कुल कितने कंज्यूमर हैं। उसके जवाब में बताया गया था कि 37-38 लाख हाउसहोल्ड कंज्यूमर हैं तथा कनेक्शन्स के बारे में पूछा तो बताया गया कि कनेक्शन्स लगभग सवा 9 लाख लोगों के पास हैं और उन सवा 9 लाख में से भी साढ़े 8 लाख तो वे अनुसूचित जाति के कनेक्शन्स हैं जो सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिये हुये हैं। इसका मतलब यह है कि उस पानी को गांवों में लगभग 35 लाख लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और उनके पास कनेक्शन्स तो सिर्फ 50 हजार हैं और बाकी सब अनअर्थोराइज चल रहे हैं। उन अनअर्थोराइज में भी केवल बाहर की टूटी का पानी थैस्ट नहीं होता बल्कि वहाँ से मकान मालिक अपने घर के अन्दर पाईप ले जाता है और अन्दर भी उसके ऊपर टूटी नहीं लगाता। जब तक उसको जरूरत होती है पानी यूज करता है और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती है तो वह पानी ऐसे ही बेकार बहता छोड़ देता है, वह उस पर टूटी नहीं लगाता। वह पानी गली में ऐसे बहता रहता है जैसे कोई नाला बंद रहा हो। इसको रोकने के लिए मेरा एक सुझाव है कि इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन तथा

[प्रो. सम्पत सिंह]

अधिकारियों का सहयोग जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जो नये वॉटर वर्क्स के लिए बिजली के कनेक्शन्स की बात हो रही थी कि कनेक्शन्स लैट हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वॉटर वर्क्स के लिए हमें सैनेटरी बोर्ड से मंजूरियाँ भी मिल रही हैं और पैसा भी खूब मिल रहा है। पब्लिक हेल्थ बिजली निगमों में कनेक्शन्स के लिए पैसा जमा करवा देता है उसके बावजूद भी 3-3 महीने तक कनेक्शन नहीं मिलते। मेरा सुझाव है कि बिजली निगमों के साथ कोई तालमेल करके उनको आप टाईम बाउंड कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी कनेक्शन्स मिल सकें। जब पैसा जमा करवा दिया है तो समय पर कनेक्शन भी मिलना चाहिए। लेकिन वे 3-3 महीने तक कनेक्शन नहीं देते हैं।

Mr. Speaker : Hon'ble Minister, suggestions may be noted please.

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रो. सम्पत सिंह जी जो समस्या उठा रहे हैं और जो सुझाव दे रहे हैं उसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि इस बारे में हमारी हर दूसरे महीने मीटिंग होती है और अब तो कनेक्शन्स बहुत कम रह गये हैं। वे कनेक्शन पॉवर डिपार्टमेंट को देने हैं जैसे ही कनेक्शन मिल जायेंगे हम उनको चालू कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने यह कही थी कि पानी के अनअथॉराइज्ड कनेक्शन्स चल रहे हैं, अगर माननीय साथी अपने इलाके के अनअथॉराइज्ड कनेक्शन्स के बारे में लिख कर दे दें तो मैं सदन के पटल पर यह आश्वासन देती हूँ कि मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

प्रो. सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता। इसमें तो सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग जरूरी है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये खुद करेंगे नहीं और दूसरों को करने नहीं देंगे।
(हंसी)

Drinking Water and Sewerage Facility in Julana

***1940 Shri Parminder Singh Dhull:** Will the Public Health Engineering Minister to be pleased to state :—

- (a) The time by which proper drinking water facility and sewerage system is likely to be provided in Julana Town;
- (b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the aforesaid facilities of water and Sewerage to the residents of Shadipur Jullana and the colonies across the railway line; and
- (c) If so, the time by which booster for drinking water is likely to be installed in the said area?

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी) :

- (क) श्रीमान जी। जुलाना शहर में जल आपूर्ति में वृद्धि और सीवरेज सुविधा के चल रहे कार्यों को 30-6-2014 तक पूर्ण किए जाने तथा शुरु हो जाने की संभावना है।
- (ख) जल आपूर्ति और सीवरेज के कार्य जो कि ऊपर (क) में वर्णित में शादीपुर जुलाना शामिल है। रेलवे पार कालोनियों में जल आपूर्ति और सीवरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।
- (ग) शादीपुर जुलाना में बुस्टिंग स्टेशन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा 30-6-2014 तक पूरा होने की संभावना/शुरु करने की संभावना है।

श्री परमिन्द्र सिंह दुल : अध्यक्ष महोदय, लाईन पार की कालोनी बहुत बड़ी कालोनी है और वर्षों से उनकी पानी की डिमांड है। सरकार ने पैसा खर्च करके रेलवे लाईन के नीचे से पानी की लाईन पहुंचाई हुई है और उसके बावजूद भी वहाँ पर पानी न मिले तो यह गलत बात है। वह अथॉराइज कालोनी है और वहाँ पर सीवरेज का काम भी पूरा हो चुका है तथा वहाँ पर पानी की बहुत जरूरत है। वहाँ पर बूस्टर स्टेशन बनना है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि लाईन पार की अथॉराइज कालोनी जो नगरपालिका क्षेत्र में पड़ती है, मैं क्या बूस्टर स्टेशन बना कर पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करेंगे और दूसरी बात है कि जुलाना टाऊन में सीवरेज लाईन व पीने के पानी की लाईन बिछाने के लिए पिछले दो अर्द्ध साल से सभी गलियों और सड़कों को तोड़ दिया गया है, पब्लिक हेल्थ के इस काम की वजह से जिन गलियों और सड़कों को तोड़ा गया है क्या इसी दौरान (30.6.2014 तक) उनका भी पुनर्निर्माण किया जायेगा ?

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहती हूँ कि जुलाना के अन्दर तो पानी की स्थिति बहुत ही अच्छी है i.e. 88 litres per capita per day. It is very very good, considering rest of the areas. सैकेंडली इन्होंने जो रेलवे कॉलोनी के पास की कॉलोनी का जिक्र किया है उसके बारे में मेरे को जो बताया गया वह अनअथॉराइज कॉलोनी है but if it is an authorized colony. We will certainly look into it. I say that very emphatically, if it is an authoriesd colony, we will lay pipe lines there. Secondly, जो वे प्रोवाइडिंग ऑफ वाटर सप्लाई और सीवरेज की स्कीम चल रही हैं, he must know about it. Both Schemes are likely to be completed by 30.6.2014. इसके बाद इनको सीवरेज व पानी की शारी सुविधाएं मिल जाएंगी। जहां तक सड़कों का सवाल है सड़कें बनाना पी.डब्ल्यू डिपार्टमेंट का काम है क्योंकि हमारा विभाग सड़कों का पैसा पी.डब्ल्यू.डी. विभाग को दे देता है।

Construction of Embankments of Markanda River

*1834. Sh Rajbir Singh Brara : Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct embankments of Markanda river from village Hemamajra to N.H. 73 in Mullana Constituency; if so the time by which the aforesaid embankments are likely to be constructed/completed?

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chatta) : No, Sir.

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : स्पीकर सर, मैंने प्रश्न लगाया था जिसका मंत्री जी ने 'नो' में जवाब दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे इल्के में मुलाना में भारकंडा नदी है जो मुलाना हल्का के बीचों बीच जाती है। जब भारकंडा नदी उफान पर होती है उस समय जिस एरिया में पटरी बनी हुई है वहां की फसल बच जाती है। अध्यक्ष महोदय, एक हेमा माजरा गांव है जो एन.एच. 73 के नजदीक है, उस गांव के दो किलो मीटर का एरिया के बीच तीन-चार गांव और आते हैं जिनमें हर बार दो से तीन-चार फुट पानी भर जाता है। वहां के मकान भी खराब हो जाते हैं और वहां पर मिट्टी चढ़ने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं। चड्ढा साहब का तो मुलाना से वैसे भी संबंध है तो चड्ढा साहब तो इस बारे में बता भी देंगे।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : स्पीकर सर, बराड़ा साहब की बात में वजन है कि वहां डेढ़-दो किलो मीटर लम्बी लाईन ऐसी है जहां बांध बना हुआ नहीं है। बांध न बनने के दो कारण हैं एक तो यह कि उन गांवों में पानी कम जाता है और हेमा माजरा गांव में तो पानी कमी नहीं जाता और जाता भी है तो जमीन की सतह तक जाता है और जल्दी वापस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि वहां के लोग लैंड एक्वायर नहीं करने देते। अगर वहां के लोग बांध बनाने के लिए जमीन दे दें तो हम कंसीडर कर सकते हैं। बराड़ा साहब पहले वायदा करें कि हम जमीन देंगे तो हम कंसीडर कर सकते हैं।

श्री राजबीर सिंह बराड़ा : स्पीकर सर, चड्ढा साहब कह रहे हैं कि पानी नहीं जाता तो मैं कल आपको वहां के फोटोग्राफ दूंगा कि वहां पर कितना-कितना पानी है और चड्ढा साहब, आप अपने महकमें से पूछ लेना वहां पर 3 या 4 फुट पानी जाता है। मैं आपके पास फोटोग्राफ भिजवा दूंगा आप देख लेना कि वहां कितनी फसल खराब हुई है और कितना पानी वहां पर पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप फोटोग्राफ्स भेज दीजिए।

श्री राजपाल भूखड़ी : स्पीकर सर, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यही सेम प्रोब्लम मेरे क्षेत्र में भी है। मेरे क्षेत्र में लाहड़पुर और रामपुर गांव हैं जहां पर भूमि कटाव बहुत ज्यादा होता है और वहां के किसानों को हर वर्ष नुकसान होता है। क्या मंत्री जी उसके लिए भी कुछ करेंगे ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : मुझे आप लिख कर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दीजिए।

श्री मामू राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि नीलोखेड़ी हल्के के अन्दर सिरसा ब्रांच है और सिकरी गांव से लेकर रायसन गांव तक आठ पुल बने हुए हैं और वह पुल सन् 1857 के समय के बने हुए हैं जो कि बिल्कुल खंडहर हो चुके हैं जिससे कई हादसे हो चुके हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उन पुलों का निर्माण कब तक किया जाएगा ?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं खुश किस्मत हूँ कि यह कार्य मेरे अण्डर है अगर मामू राम जी, एक वफा भी मुझे कह देते कि इन पुलों की स्थिति को देख लो, इनको ठीक करवा दो तो मैं 10 बार देखने को तैयार हूँ क्योंकि यह मेरा काम है।

श्री अध्यक्ष : आप लिख कर दे दो।

Fertilizer Centre of IFFCO in Loharu

***1935. Master Dharampal Obra:** Will the Agriculture Minister be pleased to state—

- (a) Whether it is a fact that the fertilizer centre of IFFCO was established in Loharu Town of Loharu constituency but it has been closed since the last one year; and
- (b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to restart the IFFCO fertilizer centre at Loharu Town which stands closed for that last one year and whether any new IFFCO fertilizer centres are also likely to be established in Behal and Siwani of Loharu constituency?

Agriculture Minister (Sardar Paramvir Singh): This question is in two parts and the answer to first part is 'Yes Sir,' The fertilizer Centre of IFFCO has been closed down and the answer to part B is 'No Sir.'

मास्टर धर्मपाल ओबरा : स्पीकर सर, लोहारु कस्बे में इफको का उर्वरक केन्द्र खोला गया था जो एक साल से ज्यादा समय से बंद पड़ा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इससे किसान बड़े परेशान होते हैं। इसलिए वह कब तक दोबारा खोला जाएगा, अगर बंद कर दिया तो क्यों कर दिया?

15.00 बजे **सरदार परमवीर सिंह :** स्पीकर सर, लोहारु कस्बे में इफको का उर्वरक केन्द्र बंद करने के संबंध में मैं हमारे नानगीय साथी को बताना चाहूंगा कि इफको ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया है कि उनको तीन साल से लगातार हेवी लॉसिज फेस करने पड़ रहे थे जिसके कारण यह केन्द्र बंद करना पड़ा है। इसके साथ ही साथ यह भी इन्फॉर्म किया गया कि वहां पर (लोहारु कस्बे में) जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसायटी और हेफेड के सेंटर हैं उनमें यथासंभव खाद अवेलेबल है।

Mr. Speaker : Thank you, Hon'ble Minister. Now, the question hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

***1896. Shri Pardeep Choudhary :** Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Multistorey Parking on the Parking Site on Mini Secretariat Panchkula; if so, the time by which aforesaid multistorey parking is likely to be constructed?

राजस्व मंत्री (श्री महेन्द्र प्रताप सिंह) : जी हाँ, बहुमंजिला पार्किंग लगभग तीन वर्ष में निर्मित हो जायेगी।

To Set Up a Timber Market in Yamunanagar

***1874. Shri Dilbag Singh:** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Timber Market in Yamuna Nagar?

कृषि मंत्री (सरदार परमवीर सिंह) : जी हां, श्रीमान्।

New Ambulance at PHC Dhamtan

***1867. Shri Pirthi Singh Nambardar :** Will the Health Minister be pleased to state—

- (a) Whether it is a fact that the Ambulance of PHC Dhamtan (Narwana Constituency) provided under the Gramin Swasth Mission has been condemned; and
- (b) If so, whether a new Ambulance will be provided in the PHC as at (a) above together with the time by which a new ambulance is likely to be provided?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

(क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्तर (क) के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

Policy of Replacement of Transformers

***1847. Dr. Ashok Kashyap:** Will the Power Minister be pleased to state:

- (a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to make a policy or to fix time limit for replacement of burnt/stolen transformers of the farmers especially during paddy season; and
- (b) If so, the time by which the policy is likely to be framed?

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

(क) तथा (ख) श्रीमान् धान के मौसम के दौरान विशेषकर किसानों के जले/चोरी हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए समय-सीमा निश्चित करने अथवा नीति बनाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टों के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों एवं कृषि श्रेणी में 48 घण्टों के अन्दर जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने का हमारा प्रयास है। चोरी हुए ट्रांसफार्मरों के मामले में, इनको उपभोक्ताओं द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करवाने तथा 20 प्रतिशत लागत जमा करवाने के बाद बदला जाता है।

Repair of Roads in Pataudi Constituency

***1929. Shri Ganga Ram :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the roads in the Pataudi Constituency; if so, the time by which these roads are likely to be repaired?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

नहीं, श्रीमान जी।

पटौदी निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों की कुल लम्बाई 293.53 कि०मी० है:

- (i) 136.85 कि०मी० सड़कों की लम्बाई अच्छी हालत में है।
- (ii) 72.60 कि०मी० सड़कों की लम्बाई संतोषजनक हालत में है और पैच कार्य का रख-रखाव किया जा रहा है।
- (iii) 21.11 करोड़ रुपये की लागत के 18.17 कि०मी० लम्बाई के कार्य प्रगति पर हैं और 31.08.2014 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।
- (iv) 31.47 कि०मी० लम्बी सड़कों की निविदाएं 25.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्राप्त हो चुकी हैं और प्रक्रिया में है।
1.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 12.99 कि०मी० लम्बाई की निविदाएं 10.03.2014 तक आमंत्रित की गई हैं जिनकी समय सीमा 4 महीने है।
2.92 करोड़ रुपये की लागत से 3.00 कि०मी० लम्बी सड़क को चौड़ा व मजबूतीकरण करने के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं और प्रक्रिया में है। निविदाएं आगामी वित्त वर्ष में मांगी जायेगी।
- (v) 18.45 कि०मी० लम्बाई की स्थिति असंतोषजनक है। जिसे सुधार के लिए आगामी वित्त वर्ष में लिया जायेगा।

Pending Power Bills

***1806. Shri Abhay Singh Chantala :** Will the Power Minister be pleased to state:—

- (a) The district-wise details of pending bills of power/electricity in each sector i.e. domestic, agriculture, industries, separately in the State from the period from 1-4-2005 till date; and
- (b) The detail of action taken to recover the amount of pending bill as at (a) above?

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

श्रीमान, विवरण सदन के घटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

- (क) राज्य में दिनांक 1-4-2005 से 30-11-2013 तक घरेलू, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के लंबित बिलों का जिलावार विवरण अनुबंध-ए पर दिया गया है।
- (ख) लंबित बिजली बिलों की धनराशि वसूल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
1. सरचार्ज/मुकद्दमेबाजी की प्रक्रिया से बचने के लिए अनुबंधित समय के अन्दर बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए उपभोक्ताओं को शिक्षित किया जा रहा है।
 2. बकायादार उपभोक्ताओं के अस्थाई/स्थायी रूप से कनेक्शन काटने के आदेश दिए जा रहे हैं।
 3. बकायादार परिसरों पर नए कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे हैं, जब तक पूरी बकाया धन राशि का भुगतान जमा नहीं करवाया जाता।
 4. जहां पर उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन काटने के लिए कोई विरोध किया जाता है, तो वहां जिला प्रशासन की सहायता ली जाती है।
 5. स्थाई रूप से कनेक्शन काटने के आदेश के मामले में निगम के पास रखी हुई सिक्योरिटी डिपॉजिट/अग्रिम खपत डिपॉजिट को बकाया डिफाल्टिंग धनराशि के विरुद्ध समायोजित किया जा रहा है।
 6. वर्ष 2005 से 2008 तक एक माफी योजना लागू की गई थी, जिसमें बकाया धनराशि को माफ करने के बाद ग्रामीण घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को नियमित रूप से भुगतान करने के लिए सक्षम किया गया।
 7. वर्तमान समय में, ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान योजना भी लागू की गई है।

अनुबंध-ए
धनराशि लाख रुपये में

लखित बिजली के बिल (मार्च के अंत तक)

| क्र० सं० | जिले का नाम | श्रेणी | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | नवंबर-13 तक | |
|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | फरीदाबाद | घरेलू | 12513.43 | 14404.61 | 16215.49 | 15239.95 | 13741.30 | 14286.34 | 16677.39 | 18404.71 | 21675.20 | 21641.48 | |
| | | कृषि | 517.65 | 631.21 | 566.68 | 253.11 | 277.59 | 308.47 | 355.59 | 355.59 | 396.93 | 447.34 | 490.73 |
| | | औद्योगिक | 1209.18 | 1427.71 | 1387.21 | 1238.62 | 2339.99 | 2630.54 | 3206.38 | 3206.38 | 3439.03 | 4049.43 | 3975.56 |
| 2 | एलखल | घरेलू | 2347.25 | 3028.16 | 3000.89 | 2971.40 | 3387.11 | 3807.26 | 4403.83 | 4582.59 | 4986.24 | 4986.24 | 5125.40 |
| | | कृषि | 247.45 | 297.43 | 154.77 | 155.39 | 200.38 | 228.66 | 242.06 | 270.88 | 270.88 | 301.68 | 303.96 |
| | | औद्योगिक | 150.01 | 175.72 | 130.61 | 131.51 | 248.76 | 280.92 | 294.21 | 294.21 | 360.43 | 484.77 | 693.98 |
| 3 | गुड़गांव | घरेलू | 3483.45 | 4159.79 | 3986.69 | 6083.76 | 4195.91 | 4000.45 | 4702.60 | 557.61 | 6646.59 | 8413.78 | 12937.84 |
| | | कृषि | 531.86 | 606.83 | 568.95 | 485.74 | 433.09 | 484.55 | 983.51 | 1369.66 | 1112.94 | 1121.00 | 1235.07 |
| | | औद्योगिक | 1285.24 | 1383.71 | 1550.64 | 1763.94 | 1023.90 | 983.51 | 3912.25 | 4021.90 | 2781.53 | 2336.34 | 4895.15 |
| 4 | मेवात | घरेलू | 3231.85 | 3585.05 | 3503.37 | 2117.44 | 3891.89 | 3912.25 | 4021.90 | 4021.90 | 2590.46 | 2768.11 | 4300.42 |
| | | कृषि | 525.51 | 506.68 | 709.90 | 578.88 | 395.72 | 424.45 | 536.79 | 536.79 | 144.11 | 174.01 | 264.82 |
| | | औद्योगिक | 491.59 | 542.41 | 717.52 | 840.01 | 661.77 | 699.37 | 827.73 | 827.73 | 466.74 | 588.27 | 864.13 |
| 5 | रेवाड़ी | घरेलू | 2152.72 | 3339.44 | 3712.57 | 3085.47 | 3606.60 | 3974.74 | 4630.59 | 5585.19 | 6224.24 | 6377.36 | 6377.36 |
| | | कृषि | 560.11 | 928.74 | 1005.58 | 577.90 | 457.28 | 479.63 | 494.48 | 520.13 | 520.13 | 561.58 | 651.98 |
| | | औद्योगिक | 377.63 | 436.53 | 420.37 | 426.69 | 413.96 | 416.12 | 522.95 | 492.22 | 526.30 | 526.30 | 563.03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 | महेन्द्रगढ़ | घरेलू | 4994.92 | 7259.22 | 7765.83 | 4677.01 | 5626.41 | 6169.67 | 7156.10 | 7792.47 | 8614.68 | 9112.07 |
| | | कृषि | 2735.68 | 4004.71 | 2949.87 | 767.90 | 939.55 | 1135.15 | 1363.48 | 1512.06 | 1756.06 | 1786.14 |
| | | औद्योगिक | 516.48 | 478.27 | 557.44 | 422.92 | 403.34 | 460.84 | 497.25 | 505.66 | 531.13 | 544.76 |
| 7 | भिवानी | घरेलू | 19274.88 | 26428.70 | 33359.99 | 20537.97 | 23766.91 | 29429.56 | 32921.74 | 38053.04 | 44540.80 | 48561.70 |
| | | कृषि | 11215.80 | 14502.44 | 10040.91 | 1063.40 | 1327.09 | 1614.65 | 1941.29 | 2236.63 | 2462.63 | 1787.08 |
| | | औद्योगिक | 2499.47 | 2875.78 | 3328.35 | 2654.85 | 2393.63 | 2440.94 | 2842.99 | 2774.28 | 3158.04 | 3023.69 |
| 8 | हिसार | घरेलू | 10842.70 | 14277.54 | 15555.91 | 15723.79 | 18426.69 | 21295.35 | 24659.87 | 28632.07 | 36738.65 | 42183.20 |
| | | कृषि | 629.59 | 781.83 | 286.96 | 154.80 | 131.72 | 174.54 | 233.62 | 286.22 | 361.80 | 381.56 |
| | | औद्योगिक | 936.39 | 722.00 | 854.62 | 737.80 | 850.83 | 807.43 | 812.31 | 745.57 | 829.62 | 629.70 |
| 9 | फतेहवाह | घरेलू | 2137.13 | 3259.27 | 4327.15 | 4120.18 | 4659.63 | 5220.73 | 6046.07 | 6843.92 | 7407.37 | 8239.30 |
| | | कृषि | 726.73 | 1023.27 | 1132.41 | 445.26 | 544.01 | 607.86 | 695.51 | 728.03 | 596.73 | 527.04 |
| | | औद्योगिक | 307.76 | 219.56 | 227.96 | 143.10 | 239.45 | 265.10 | 232.47 | 249.50 | 212.70 | 155.22 |
| 10 | तिरुसा | घरेलू | 1283.43 | 1391.97 | 1294.20 | 1180.01 | 1236.47 | 1340.82 | 1570.69 | 1962.94 | 2080.04 | 2574.63 |
| | | कृषि | 822.83 | 921.10 | 871.82 | 69.64 | 111.96 | 111.53 | 191.14 | 215.46 | 217.87 | 278.29 |
| | | औद्योगिक | 216.14 | 197.53 | 243.74 | 228.16 | 234.32 | 232.12 | 272.33 | 273.04 | 251.94 | 289.36 |
| 11 | जीन्द | घरेलू | 32082.85 | 41597.19 | 40535.03 | 41689.40 | 48594.53 | 56986.75 | 65951.53 | 76032.45 | 74644.57 | 82342.73 |
| | | कृषि | 6133.66 | 7651.44 | 3545.97 | 1783.17 | 1658.06 | 1877.44 | 1783.23 | 2178.63 | 2222.95 | 2086.37 |
| | | औद्योगिक | 878.84 | 978.16 | 976.16 | 986.36 | 984.46 | 1013.81 | 901.16 | 997.82 | 1025.45 | 917.32 |
| 12 | अम्बाला एवं पंचकुला | घरेलू | 701.48 | 784.58 | 831.70 | 989.71 | 1332.87 | 1599.20 | 1776.18 | 2245.53 | 2691.76 | 3291.05 |
| | | कृषि | 278.95 | 285.48 | 148.60 | 81.18 | 162.42 | 266.23 | 269.55 | 330.26 | 357.96 | 360.31 |
| | | औद्योगिक | 568.79 | 418.82 | 431.25 | 515.31 | 548.17 | 397.54 | 327.98 | 313.16 | 499.89 | 659.35 |

Repair of Roads

***1810. Shri Mama Ram :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that the following roads in Nilokheri constituency are in very bad condition:—

- (i) Jamba to Kirmach;
- (ii) Shamgarh to Tarori;
- (iii) Sandhir to Amargarh;
- (iv) Kamalpur to Aibla Jagir;
- (v) Singra to Motia; and

(b) If so, the time by which the abovesaid roads are likely to be repaired?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

श्रीमान जी सड़क अनुसार उत्तर निम्न है :-

| क्र० सं० | सड़क का नाम | मालिकाना | लंबाई (कि०मी० में) | भाग | सड़क की स्थिति | उत्तर |
|----------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | जाम्बा से किरमिच | लो०नि०वि० (भ०व स०) | 3.00 | 0.000 से 3.00 | संतोषजनक | इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। |
| 2. | शामगढ़ से तरावड़ी | ह०रा०कृ० वि० बोर्ड | 3.80 | 0.00 से 3.80 | संतोषजनक | इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। |
| 3. | सण्डीर से अमरगढ़ | लो०नि०वि० (भ०व स०) | 0.86 | 0.00 से 0.86 | संतोषजनक नहीं | इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। फिर भी इस सड़क के मजबूतीकरण बारे अगले वर्ष में विचार किया जायेगा। |
| 4. | कमालपुर से एबलाजागीर | लो०नि०वि० (भ०वस०) | 2.50 | 0.00 से 2.50 | संतोषजनक | यह सड़क 30.5.2014 तक |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------------|--------------------|------|--------------|----------|--|
| | | | | | | दोष दायित्व अवधि के अंतर्गत है। इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। |
| 5. | सिंघड़ा से मोतिया | | | | | |
| | (क) सिंघड़ा से जलाला वीरान | ह०रा०कृ० वि० बोर्ड | 4.34 | 0.00 से 4.34 | संतोषजनक | इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। |
| | (ख) मोतिया से जलाला वीरान | लो०नि०वि० (म०वस०) | 4.00 | 0.00 से 4.00 | संतोषजनक | इसका रखरखाव सामान्य पैच कार्य द्वारा किया जा रहा है। फिर भी इस सड़क को चौड़ा करने के लिए 158.00 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार यादि क्रमांक 9/318/2013-3 बी०एंड० आर० (डब्ल्यू दिनांक 3.12.2013 को जारी की जा चुकी है। |

To set up Industrial Sector in Jind City

*1801 Dr. Hari Chand Middha : Will the Industries and Commerce Minister be pleased to state:—

- The steps being taken by the Government to set up the Industrial area/Sector on the 250 acreage of land in Jind the announcement of for which was made by the Hon'ble Chief Minister on 3rd June, 2012; and
- The time by which the work to set up aforesaid Industrial Sector is likely to be started togetherwith the details of action taken so far?

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

- (क) श्रीमान अनेकों विकल्पों की जांच की गई है तथा यह प्रस्ताव विचाराधीन है।
- (ख) किसी समय सीमा को निश्चित करना मुश्किल है क्योंकि इसमें परियोजना के लिए वर्ष 2013 के एल०ए०आर० अधिनियम के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण करने की आवश्यकता शामिल है।

अतारंकित प्रश्न एवं उत्तर

572. **Shri Sampat Singh:** Will the Health Minister be pleased to state:—

- (a) Whether all the medicines which are given free to the patients are made available in PGIMS Rohtak; if not the steps being taken by the Government to make these medicines available;
- (b) The department-wise total number of posts of doctors sanctioned in PGIMS Rohtak together with the number of posts lying vacant alongwith the time by which these posts are likely to be filled up;
- (c) Since when the MRI machine is out of order together with the time within which this machine will start functioning alongwith the period for which one City Scan machine remained out of order in PGIMS; and
- (d) The time by which the Trauma Centre at the PGIMS, Rohtak is likely to start functioning?

स्वास्थ्य मंत्री (राव नरेन्द्र सिंह) :

- (क) इस समय पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक में मरीजों के लिए लगभग 230 दवायें उपलब्ध हैं। लगभग 205 दवाओं के सप्लाय आदेश दिए हुए हैं। 15 कीमोथैरपी दवायें कैंसर रोगियों को और 65 दवायें जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी प्रसव मामलों में मुफ्त दी जा रही हैं।
- (ख) विभाग अनुसार डाक्टरों की सूची सदन के पटल पर रखी गई है। रिक्त पदों के बारे कई बार विज्ञापन दिए गए परन्तु उपयुक्त/योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण भरे नहीं जा सके। तथापि, शिक्षण संकाय के डाक्टरों के रिक्त पदों के लिए शीघ्र ही पुनः विज्ञापन दिया जायेगा और उन्हें भरने के प्रयास किये जायेंगे।
- (ग) पं० बी०डी० शर्मा, पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में लगी एम०आर०आई० मशीन दिनांक 2-1-2014 को खराब हो थी जिसे दिनांक 18-1-2014 को चालू करा दिया गया।
- (घ) ट्रोमा सेंटर के माह मई/जून, 2014 तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है। ट्रोमा सेंटर भवन का कार्य, जिसमें बिजली, सिविल और जन स्वास्थ्य कार्य शामिल हैं: पूर्ण हो चुका है।

विभाग अनुसार डाक्टरों के स्वीकृत और रिक्त पद

| क्र० सं० | विभाग का नाम | सीनियर प्रोफेसर | | | डीनर | | | डाक्टरों के कुल पद | | | |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|----|
| | | स्वीकृत हुए | भरे हुए | रिक्त | स्वीकृत हुए | भरे हुए | रिक्त | स्वीकृत हुए | भरे हुए | रिक्त | |
| नियमित अनुबंध | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Anesthesiology | 04 | 04 | 0 | 28 | 21 | 00 | 07 | 32 | 25 | 07 |
| 2. | Anatomy | 01 | 01 | 0 | 12 | 10 | 00 | 02 | 13 | 11 | 02 |
| 3. | Biochemistry | 01 | 01 | 0 | 10 | 08 | 00 | 02 | 11 | 09 | 02 |
| 4. | Biotechnology | 01 | 0 | 01 | 09-1 | 3 | 01 | 5-1 | 09 | 04 | 05 |
| 5. | Blood Bank | 0 | 0 | 0 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 0 |
| 6. | Burns & plastic Surgery | 01 | 01 | 0 | 05 | 03 | 00 | 02 | 06 | 04 | 02 |
| 7. | Cardiac Surgery | 01 | 01 | 0 | 02 | 01 | 02 | 01 | 03 | 04 | — |
| 8. | Cardiology | 01 | 01 | 0 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 02 |
| 9. | Chet & T.B. | 01 | 01 | 0 | 04 | 03 | 00 | 01 | 05 | 04 | 01 |
| 10. | CT.Hematology | 01 | 0 | 01 | 02 | 0 | 00 | 02 | 03 | 01 | 02 |
| 11. | DNA Lab | - | - | - | 01 | - | 00 | 01 | 01 | - | 01 |
| 12. | Endocrinology | 01 | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 |
| 13. | E.N.T. | 01 | 01 | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 | 06 | 06 | - |
| 14. | Forensic Medicine | 01 | 01 | 0 | 06 | 06 | 00 | 00 | 07 | 07 | - |
| 15. | Gastroenterology | 01 | 0 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 |
| 16. | Hospital Admn. | 01 | 0 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 |
| 17. | Medicine | 07 | 06 | 01 | 15 | 13 | 00 | 02 | 22 | 19 | 03 |
| 18. | Medicine(A&E) | 01 | 00 | 01 | 01 | 0 | 00 | 01 | 02 | - | 02 |
| 19. | Medical Oncolgy | 01 | 0 | 01 | 01 | 0 | 00 | 01 | 02 | - | 02 |
| 20. | Immunology | - | - | - | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | - |
| 21. | Microbiology | 01 | 01 | 0 | 07 | 07 | 00 | 00 | 08 | 08 | - |
| 22. | Nephrology | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 |
| 23. | Neurology | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 01 | 02 |
| 24. | Neuro Surgery | 01 | 00 | 01 | 04 | 02 | 00 | 02 | 05 | 02 | 03 |
| 25. | Nuclear Medicine | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 03 | 01 | 02 |
| 26. | Obst. & Gyane | 03 | 03 | 00 | 15 | 14 | 00 | 01 | 18 | 17 | 01 |

[राव नरेन्द्र सिंह]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------------|----|----|----|-------------------------------------|------|----|------------|----|------------|------------|-----------|
| 27. R.O | | | | | | | | | | | |
| Ophthalmology | | | | | | | | | 15 | 15 | — |
| (a)Medical | 04 | 04 | 00 | 11 | 11 | 00 | 00 | 02 | 02 | — | 02 |
| (b)Non-Medical | — | — | — | 02 | — | — | — | — | — | — | — |
| 28. Orthopaedics | 04 | 04 | 00 | 09 | 09 | 02 | 00 | 00 | 13 | 06 | 07 |
| 29. Paediatric Surgery | 01 | 01 | 0 | 03 | 02 | 00 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
| 30. Paediatrics | 02 | 02 | 00 | 12 | 11 | 00 | 01 | 01 | 14 | 13 | 01 |
| 31. Pulmonary & Critical Care Unit | 01 | 01 | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 03 | 01 | 02 |
| 32. Pathology | 02 | 02 | 0 | 12 | 12 | 01 | 00 | 00 | 14 | 14 | — |
| 33. Pharmacology | 01 | 01 | 0 | 09 | 07 | 00 | 02 | 02 | 10 | 08 | 02 |
| 34. Physiology | 01 | 01 | 0 | 13+ 1 | 10 | — | 03+1= 4 | 15 | 11 | 04 | 04 |
| 35. Psyschiatry | 02 | 02 | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 | — |
| 36. Radiodiagnosis | 02 | 02 | 00 | 08 | 04 | 00 | 04 | 04 | 10 | 06 | 04 |
| 37. Radiotherapy | 02 | 02 | 00 | 05 | 05 | 00 | 00 | 00 | 07 | 07 | — |
| 38. Rheumatology | 01 | — | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | — | — | 02 |
| 39. Com. Medicine | 02 | 02 | 00 | 09+1 | 09+1 | 00 | 00 | 00 | 12 | 12 | — |
| 40. Skin & V.D. | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 01 |
| 41. Surgery | 06 | 06 | 00 | 15 | 14 | 01 | 01 | 01 | 21 | 20 | 01 |
| 42. Surgical Gastroenterology | 01 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 02 | — | — | 02 |
| 43. Surgical Oncology | 01 | 00 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 03 | — | 03 |
| 44. Urology | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 |
| 45. Floating Sr. Professor | 05 | 04 | 01 | — | — | — | — | — | 05 | 04 | 01 |
| 46. College of Pharmacy | 01 | 01 | 01 | 11 | 06 | 00 | 05 | 05 | 12 | 07 | 05 |
| | | | | Principal College of Pharmacy | | | | | | | |
| 47. College of Physiotherapy | — | — | — | 09 | 09 | 00 | 00 | 00 | 09 | 09 | — |
| Total | | | | | | | | | 362 | 280 | 83 |

पी०जी०आई०एम०एस० रोहतक में कार्यरत फुटकर कैटेगरी डाक्टरों की सूची

| क्र० संख्या | पद/विभाग का नाम | स्वीकृत | भरे हुए | रिक्त | टिप्पणी |
|-------------|-------------------------------|---------|---------|-------|--|
| 1. | Psychiatrist | 01 | 00 | 01 | Post already advertised and fill up very soon. |
| 2. | Deputy Medical Superintendent | 02 | 00 | 02 | Post already advertised and fill up very soon. |
| 3. | Casualty Medical Officer | 05 | 05 | 00 | — |

पी०जी०आई०एम०एस०, रोहतक में स्पेशल्टी अनुसार सीनियर रेजीडेंट/डैमोनस्ट्रेटर (डाक्टर) के रिक्त पदों की स्थिति

| क्र० सं० | विभाग का नाम | स्वीकृत | भरे हुए | | कुल रिक्त |
|----------|--------------------------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | Tenure | Contract | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sr. Resident | | | | |
| 1. | Anesthesiology | 27 | 08 | - | 19 |
| 2. | Burns & Plastic Surgery | 01 | 00 | 00 | 01 |
| 3. | Cardiac Surgery | 02 | 00 | 00 | 02 |
| 4. | Cardiology+Cath Lab | 04 | 01 | 00 | 03 |
| 5. | (A&E) Surgical & Medical | 04 | 00 | 00 | 04 |
| | Orthopedics | 02 | 01 | 00 | 01 |
| | Obst. & Gyanae | 02 | 01 | 00 | 01 |
| | Medicine | 02 | 00 | 00 | 02 |
| | Pediatrics | 02 | 00 | 00 | 02 |
| 6. | Clinical Hematology | 01 | 00 | 00 | 01 |
| 7. | E.N.T. | 02 | 03 | 00 | 00 |
| 8. | Gastroenterology | 01 | 01 | 00 | 00 |
| 9. | Endocrinology | 01 | 00 | 00 | 01 |
| 10. | General Surgery | 20 | 06 | 00 | 14 |
| 11. | Hospital Administration | 01 | 00 | 00 | 01 |
| 12. | Medical Oncology | 01 | 01 | 00 | 00 |

[श्रीव नरेन्द्र सिंह]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|------------------------------|-----------|----|----|-----|
| 13. | Medicine | 20 | 09 | 00 | 11 |
| 14. | Nephrology | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 15. | Neurology | 01 | 01 | 00 | 00 |
| 16. | Neuro-Surgery | 02 | 01 | 00 | 01 |
| 17. | Nuclear Medicine | 02 | 00 | 01 | 01 |
| 18. | Obst. & Gynae | 11 | 11 | 00 | 00 |
| 19. | Orthopaedics | 07 | 11 | 00 | 00 |
| 20. | Paediatric Surgery | *02 | 00 | 00 | 02 |
| 21. | Paediatrics | *017-2=15 | 04 | 00 | 11 |
| 22. | Psychiatry | 04 | 03 | 00 | 01 |
| 23. | Pulmonary & Cr. Care Med. | *04 | 03 | 00 | 01 |
| 24. | R.I. Ophthalmology | 11 | 04 | 00 | 07 |
| 25. | Radiology+MRI | 08 | 03 | 00 | 05 |
| 26. | Radiotherapy | 05 | 02 | 00 | 03 |
| 27. | Rheumatology | 01 | 01 | 00 | 00 |
| 28. | Community Medicine | 06 | 04 | 00 | 02 |
| 29. | Skin & V.D. | 03 | 01 | 02 | 00 |
| 30. | Surgical Gastroenterology | 02 | 00 | 00 | 02 |
| 31. | Surgical Oncology | 02 | 01 | 00 | 01 |
| 32. | T.B. & Resp. Medicine | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 33. | Urology | 02 | 02 | 00 | 00 |
| 34. | Gen. ICU | *04 | 00 | 00 | 04 |
| कुल जोड़ | | 187 | 84 | 03 | 107 |

House Tax on Flats

571. Shri Devender Kumar Bansal: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:

- (a) Whether it is a fact that House Tax on Flats is being charged on per square feet basis;
- (b) Whether it is also a fact that House Tax is being charged on houses on per square metre basis ;
- (c) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to charges House Tax on per square metre basis on the flats at in the case of houses?

(शहरी स्थानीय निकाय मंत्री) श्रीमती सावित्री जिन्दल :

- (क) हाँ, श्रीमान जी।
- (ख) नहीं, श्रीमान जी, भकानों पर सम्पत्ति कर की वसूली प्रति वर्ग गज के आधार पर की जा रही है।
- (ग) नहीं, श्रीमान जी।

Regularization of 4th Class Employees

603. Col. Raghbir Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:

- (a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the 4th Class employees working on temporary basis in various Departments of the Haryana State by framing a policy; if so, the time by which these temporary employees are likely to be regularized?
- (a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to restart the old policy of ex-gratia i.e. employment benefit policy which existed before the year 1995; if so, the time by which the old policy prior to year 1995 regarding Ex-gratia benefits is likely to be re-started?

मुख्यमन्त्री (श्री मूपेन्द्र सिंह हुडा) :

- (क) व (ख) नहीं, श्रीमान जी।

Recommendation for NCDNSNT

587. Smt. Renuka Bistnoi: Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state—

- (a) The main recommendation of the National Commission for De-notified Nomadic and Semi-Nomadic Tribes (NCDNSNT) made in its report submitted to the Government in 2008;

[Smt. Renuka Bishnoi]

- (b) The reasons for delay in implementation of the recommendations of report of the NCDNSNT; and
- (c) The steps being taken by the Government to grant Scheduled Tribes status to the Nomadic and Semi-Nomadic Tribes identified by NCDNSNT and to give them reservation in Government services accordingly?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

श्रीमान जी,

- (क) राष्ट्रीय विमुक्त जाति, घुमन्तु एवं अर्ध-घुमन्तु जनजाति आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था और भारत सरकार ने उक्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों को राज्य सरकार से सझा नहीं किया।
- (ख) व (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Total Number of Students in Private Schools

573. **Shri Sampat Singh:** Will the Education Minister be pleased to state:

- (a) The total number of students in Private Schools up to Senior Secondary in the State;
- (b) The total number of Government schools where the students enrollments is less than 25;
- (c) The total number of Government schools which likely are to be closed for the want of students togetherwith the name of such schools;
- (d) The total number of Government schools which are without proper arrangement of toilets, drinking water and school desks facilities?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

श्रीमान जी,

- (क) राज्य में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के निजी विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 2021279 है।
- (ख) राज्य में ऐसा कोई सरकारी विद्यालय नहीं जिनमें छात्रों की संख्या 25 से कम हो।
- (ग) छात्रों की कम संख्या के कारण किसी भी सरकारी विद्यालय को बंद किए जाने का कोई भी प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।
- (घ) राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय उच्च विद्यालयों तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में शौचालयों तथा पीने के

पानी की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2003-04 से 2012-13 के दौरान एस0एस0ए0 द्वारा 21,922 शौचालय बनवाए गए हैं। इसी प्रकार से 5505 विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा एस0एस0ए0 द्वारा इसी समय अवधि के दौरान उपलब्ध करवाई गई है। राज्य सरकार राज्य के सभी विद्यालयों में ड्युल डैस्क उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिबद्ध है। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 2,48,015 ड्युल डैस्क, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1,57,759 ड्युल डैस्क, तथा राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 1,45,441 ड्युल डैस्क, की आवश्यकता है। वर्ष 2012-13 के दौरान लगभग 85,658 ड्युल डैस्क 7.85 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए तथा राज्य के राजकीय उच्च विद्यालयों/राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में मांग के आधार पर पूर्ति कर दी गई है। ड्युल डैस्क उपलब्ध करवाना एक स्तत प्रक्रिया है। राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु आवंटित किए गए बजट के अनुसार डैस्क की खरीद की जाती है। वर्ष 2013-14 के लिए विभाग का कुल बजट 134.88 करोड़ रुपये (सैकेण्डरी पक्ष के लिए 34.75 करोड़ रुपये तथा मौलिक शिक्षा पक्ष के लिए 100.13 करोड़ की राशि) है।

Pending Tubewell Connections in Badhra Constituency.

604. Col. Ragubir Singh : Will the Power Minister be pleased to state:

- (a) The number of Tubewell connections released in the Badhra Constituency during the period from January, 2010 to till date togetherwith number of applications for Connections which are lying pending so far;
- (b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to release the new Tubewell Connections; if so, the time by which new connections are likely to be released; and
- (c) The villagewise number of Power Houses set up in the Badhra Constituency during the period from January 2010 till date together with the capacity of these Power Houses?

बिजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) :

श्री मान जी,

| | | | |
|-----|-----|--|------|
| (क) | (1) | बाढ़ड़ा निर्वाचन क्षेत्र में जनवरी, 2010 से 31-12-2013 तक जारी किए गए नलकूप कनेक्शन | 2033 |
| | (2) | 31-12-2013 को बाढ़ड़ा निर्वाचन क्षेत्र में लंबित आवेदन (आवेदन, जिन्होंने पूरी राशि जमा करवाई | 346 |
| | | आवेदन, जिन्होंने अंतिम तिथि 31-12-2011 के बाद आवेदन किया | 20 |
| | | | 326 |

[कैप्टन अजय सिंह यादव]

- (ख) निम्न विकल्पों के साथ नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए एक नीति प्रभावी है।
- (3) 31-12-2011 (सामान्य श्रेणी) तक आवेदक जिन्होंने कनेक्शनों के लिए आवेदन किया है, को वर्तमान में कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। सभी 20 लम्बित आवेदक, जिन्होंने पूरी राशि जमा करवा दी है का कार्य प्रगति पर है। कनेक्शनों को तीन महीनों में जारी कर दिया जाएगा।
- (4) आवेदक जिन्होंने 31-12-2011 के बाद आवेदन किया था, को बाद में वरिष्ठता आधार पर कनेक्शन जारी किए जाएंगे। यद्यपि आवेदक "स्वयं निष्पादन योजना" चुन सकता है और कार्य पूरा होने के बाद कनेक्शन ले सकता है।
- (ग) जनवरी, 2010 से दिसम्बर, 2013 तक बाढ़ड़ा निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित बिजली घरों की गांववार संख्या निम्नानुसार है:

| क्रमांक | गांव का नाम | सब-स्टेशन का नाम | क्षमता | कार्यान्वयन की तिथि |
|---------|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| 1. | खुडाना | 33 के0वी0 सब-स्टेशन खुडाना | 10 एम0वी0ए0 | 7-7-10 |
| 2. | चांदवास | 33 के0वी0 सब-स्टेशन चांदवास | 10 एम0वी0ए0 | 5-12-12 |
| 3. | घसोला | 33 के0वी0 सब-स्टेशन घसोला | 10 एम0वी0ए0 | 7-01-13 |
| 4. | बेरला | 132 के0वी0 सब-स्टेशन बरेला | 50 एम0वी0ए0 | 4-4-13 |
| 5. | डाढ़ी बाना | 220 के0वी0 सब-स्टेशन डाढ़ी बाना | 200 एम0वी0ए0 | 26-1-13 |

Setting up of a Central University

588. Smt. Renuka Bishnoi : will the Education Minister be pleased to state :

- (a) Whether it is fact that Government has acquired about 500 acre fertile land in Village Jant-Pali in Mahendergarh District of Haryana for setting up of a central university; if so the details thereof;
- (b) Whether any compensation for the aforesaid land has been given and also Government service has also been given to the family members of land owners whose land has been acquired; if so, the details thereof; and
- (c) The steps being taken by the Government to provide Government service to the families affected by this project and also to give preference in admission to their children?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल):

- (क) श्रीमान जी, राज्य सरकार ने महेन्द्रगढ़ में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा स्थापित करने के लिए 55 एकड़, 3 कनाल तथा 14 मरले भूमि अर्जित की है।
- (ख) भू-स्वामियों को कुल 9 करोड़ 77 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। जिन परिवारों की भूमि अर्जित की गई है उनको सरकारी नौकरी प्रदान नहीं की गई है।
- (ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में, जिसके तहत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उन परिवारों के लिए जिनकी भूमि अर्जित की गई है किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तथापि, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली ने आश्वासन दिया है कि अधिनियम के पैमानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय आस पास के गांवों के विकास एवं वृद्धि के लिए हर सम्भव कार्य करेगा।

Number of Police Public Schools

574. Shri Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state:

- (a) The number of Police Public Schools that are running in police lines in Haryana along with the name of places where these are being run; and the class wise total number of students studying in each school;
- (b) The number of students in each of such school who are wards of police personnel and others separately;
- (c) The academic and other achievements of each of the schools;
- (d) Whether the maintenance or other fee is being charged from all the police personnel or only from those whose wards are studying there; and
- (e) The name of police lines where these schools are likely to be started?

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| IV | 50 | IV | 48 | IV | 140 | IV | 74 | IV | 105 | IV | 41 | IV | 36 |
| V | 76 | V | 59 | V | 131 | V | 66 | V | 99 | V | 41 | V | 26 |
| VI | 70 | VI | 42 | VI | 136 | VI | 64 | VI | 91 | VI | 36 | VI | 17 |
| VII | 69 | VII | 36 | VII | 140 | VII | 84 | VII | 72 | VII | 29 | VII | - |
| VIII | 65 | VIII | 70 | VIII | 121 | VIII | 72 | VIII | 37 | VIII | 25 | VIII | - |
| IX | 52 | IX | 71 | IX | 123 | IX | 88 | IX | - | IX | - | IX | - |
| X | 55 | X | 51 | X | 108 | X | 97 | X | - | X | - | X | - |
| XI | 55 | XI | - | XI | 126 | XI | 82 | XI | - | XI | - | XI | - |
| XII | 36 | XII | - | XII | 112 | XII | 46 | XII | - | XII | - | XII | - |
| कुल | 817 | कुल | 728 | कुल | 1973 | कुल | 1016 | कुल | 1086 | कुल | 484 | कुल | 303 |

(ख)

| क्रम सं० | पुलिस पब्लिक स्कूलों का नाम | पुलिस कर्मचारियों के पढ़ने वाले बच्चों की संख्या | बाहर से पढ़ने वाले बच्चों की संख्या | कुल संख्या |
|----------|---|--|-------------------------------------|------------|
| 1. | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल मधुवन, करनाल। | 426 | 391 | 817 |
| 2. | पुलिस विद्या मन्दिर स्कूल, कुरुक्षेत्र। | 190 | 538 | 728 |
| 3. | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल, अम्बाला शहर। | 575 | 1398 | 1973 |
| 4. | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल, हिसार। | 501 | 515 | 1016 |
| 5. | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल, पानीपत। | 714 | 372 | 1086 |
| 6. | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल, सुनारियां, रोहतक। | 214 | 270 | 484 |
| 7. | श्री राम पुलिस पब्लिक स्कूल, भोंडसी, गुड़गावां। | 270 | 33 | 303 |

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

(ख)

| क्र० | पुलिस पब्लिक स्कूलों का नाम। | शैक्षिक उपलब्धियां | अन्य उपलब्धियां |
|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1. | डी०ए०वी० स्कूल मधुबन, करनाल। | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल मधुबन, करनाल की कक्षा 10 और 12 का परिणाम 100 प्रतिशत है। इस स्कूल के छात्र दिवांश दलाल ने आई०आई०टी० की प्रवेश परीक्षा साल 2012 में जिला की करनाल में प्रथम स्थान हासिल किया व स्कूल के अन्य दो छात्रों का एन०डी०ए० खडकवासला में दाखिला हुआ है। | इस स्कूल के 8 छात्रों ने स्पैट के लिए क्वालीफाई किया है एवम् 1500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। तेराकी में इस स्कूल ने सहोदया स्कूल कम्पलैक्स की ओवरआल ट्राफी लगातार तीन साल विजेता रही है। इस स्कूल के छात्र हेमंत कक्षा दसवीं तथा अर्पण कक्षा नौवीं का राज्य की फुटबाल टीम में चयन हुआ है। कक्षा चौथी के छात्र ने गोल्फ प्रतियोगिता में जो कि चण्डीगढ़ में हुई थी, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। |
| 2. | पुलिस विद्या मन्दिर कुरुक्षेत्र। | स्कूल के 8 छात्रों ने कक्षा दसवीं की परीक्षा में मैरीट सूची में स्थान हासिल किया है। स्कूल के छात्र अक्षय ने जिला कुरुक्षेत्र में हुये विज्ञान मेले में तीसरा स्थान हासिल किया है। | स्कूल के छात्र रूपेश व विशाल ने जोनल स्तर की कुश्ती में क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान हासिल किया। जसप्रीत व विशाल ने जोनल स्तर की वास्केटबाल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। |
| 3. | डी०ए०वी० पुलिस पब्लिक स्कूल, अम्बाला शहर। | वर्ष 2012-13 में स्कूल ने कक्षा दसवीं की परीक्षा का परिणाम शत प्रतिशत रहा है। कक्षा बारहवीं का इकायानवे प्रतिशत रहा है। कक्षा दसवीं की हुई परीक्षा में एक सौ एक छात्रों में से अठत्तर छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुये है तथा बारहवीं की परीक्षा में एक सौ बारह छात्रों | स्कूल ने तीसरी विश्वकप मार्शल किक बाकसिंग प्रतियोगिता में 2 कांस्य व 2 रजक पदक प्राप्त किये हैं। स्कूल में छटी वरिष्ठ नेशनल सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में एक कांस्य पदक व वरिष्ठ नेशनल किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में एक कांस्य पदक प्राप्त किया। चौथी उत्तर भारत ताईकोण्डो |

| 1 | 2 | 2 | 3 |
|----|--|---|--|
| | | में से चौहत्तर छात्रों ने प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। | प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण तथा 3 रजत पदक प्राप्त किये। वर्ष 2012-13 में स्कूल ने विभिन्न जिला एवम् जोनल स्तर की प्रतियोगिताओं में कुल 91 स्वर्ण पदक, 47 कांस्य व 13 रजत पदक प्राप्त किये। |
| 4. | डी0ए0वी0 पुलिस पब्लिक स्कूल, हिसार। | वर्ष 2012-13 में कक्षा दसवीं व कक्षा बारहवीं का परिणाम शत प्रतिशत रहा है। इस स्कूल के छात्र राहुल कटारिया का एन0डी0ए0 में चयन हुआ। दो छात्रों को कक्षा बाहरवीं की भौतिकी में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने पर सी0बी0एस0ई0 द्वारा मेरिट सर्टीफिकेट प्रदान किया गया। | स्कूल की लड़कियों की टीम सी0बी0एस0ई0 राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिता में लगातार तीन वर्ष विजेता रही है। लड़कों ने सी0बी0एस0ई0 राष्ट्रीय हैंड बाल की प्रतियोगिता जीती है। एक विद्यार्थी ने सी0बी0एस0ई0 राष्ट्रीय प्रतियोगिता ताईकोण्डो में स्वर्ण पदक जीता। हैंडबाल, हाकी व ताईकोण्डो के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जीत हासिल की। जय प्रकाश ने यूथ कॉमनवैल्थ खेल, कैमरून, साउथ अफ्रीका में हिस्सा लिया। |
| 5. | डी0ए0वी0 पुलिस पब्लिक स्कूल, पानीपत। | इस स्कूल की स्थापना दो वर्ष पूर्व हुई थी। इसमें नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा में कुल 1086 छात्र हैं। | इस स्कूल ने किक-बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण 3 कांस्य तथा 2 रजत पदक प्राप्त किये। उत्तर भारत कराटे प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 3 कांस्य तथा 3 रजत पदक प्राप्त किये। |
| 6. | डी0ए0वी0 पुलिस पब्लिक स्कूल सुनारिया, रोहतक। | इस स्कूल की स्थापना 2012-13 में हुई है। इसमें प्री-के0जी0 से लेकर आठवीं कक्षा में 484 छात्र हैं। | इस स्कूल ने 2013-14 में हरियाणा राज्य अंतर विद्यालय किक बाक्सिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण 8 कांस्य तथा 10 रजत पदक प्राप्त किए। |

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

| 1 | 2 | 2 | 3 |
|----|--|---|--|
| 7. | श्री राम पुलिस पब्लिक स्कूल भोंडरी, गुड़गावां। | इस स्कूल की स्थापना वर्ष 2012-13 में हुई है। इसमें नर्सरी से लेकर छठी कक्षा तक 303 छात्र हैं। | स्कूल ने फरवरी 2013 में प्रथम श्री रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें 60 स्कूलों के 150 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस स्कूल के दो छात्रों ने कांस्य पदक जीता। |

(घ) सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से स्कूलों के रख रखाव के लिये वर्ष में एक बार हरियाणा पुलिस शिक्षा कोष के लिये कटौती की जाती है। पुलिस अधिकारी/कर्मचारी जिसके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, वे स्कूल द्वारा निर्धारित फीस व अन्य शुल्क देते हैं। उपरोक्त सभी पुलिस-पब्लिक स्कूलों में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों के लिये निर्धारित शुल्क कम है।

पद के अनुसार हरियाणा पुलिस शिक्षा कोष के लिये की जाने वाली वार्षिक कटौती निम्न प्रकार से है:

| क्र०सं० | पद | वार्षिक कटौती |
|---------|---|---------------|
| 1. | भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी | रु० 250/- |
| 2. | राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी व समकक्ष | रु० 200/- |
| 3. | सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक तक व समकक्ष | रु० 150/- |
| 4. | मुख्य सिपाही, सिपाही व वर्कक | रु० 100/- |

(च) निम्नलिखित पुलिस लाइनों में जल्द ही पुलिस स्कूल शुरु किये जाने का विचार है:

1. पुलिस लाइन, रेवाड़ी
2. पुलिस लाइन, पंचकुला
3. पुलिस लाइन, यमुनानगर
4. पुलिस लाइन, जीन्द

Allocation of Funds to the Villages

605. Col. Raghir Singh: Will the Chief Minister be pleased to State:

- (a) The villagewise amount of the funds released by the Development and Panchayats Department for the development works in the villages of Badhra Constituency during the period from 2009 to till date; and
- (d) The number of villages in which the allotted work has been completed together with the number of those villages in which the work is in progress?

डुरखडडरतुरी (शुरी डूरुडनुनुर सिह हडुडर) :

शुरीडरन डी, सूडरनर सडन डडल डर ररखी डरती हे ।

सूडरनर

(ए) शुरीडरन डी, डिवररन इस डुरकर हे:

| Sr. No. | Name of G.P. | Amount (in lacs) |
|---------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Abidpura | 7.33 |
| 2. | Arya Nagar | 23.43 |
| 3. | Asawari | 7.15 |
| 4. | Badal | 14.80 |
| 5. | Badhra | 59.30 |
| 6. | Badhwana | 29.95 |
| 7. | Badrai | 26.99 |
| 8. | Balali | 26.33 |
| 9. | Balkara | 38.68 |
| 10. | Balroad | 14.53 |
| 11. | Berla | 54.13 |
| 12. | Bhandwa | 35.76 |
| 13. | Bijna | 14.81 |
| 14. | Bilawal | 36.08 |
| 15. | Chandeni | 17.06 |
| 16. | Chandwas | 20.23 |
| 17. | Changroad | 29.61 |
| 18. | Chiriya | 36.13 |
| 19. | Dadhi Bana | 8.84 |
| 20. | Dadhi Chillar | 6.57 |
| 21. | Dagroli | 41.09 |
| 22. | Dalawas | 20.95 |
| 23. | Dandma | 27.27 |

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------|-------|
| 24. | Datoli | 10.64 |
| 25. | Dhanasari | 28.04 |
| 26. | Dhani Phogat | 42.32 |
| 27. | Dudhwa | 16.68 |
| 28. | Dwarka | 21.25 |
| 29. | Ghasola | 34.84 |
| 30. | Gokal | 5.55 |
| 31. | Gopalwas | 25.24 |
| 32. | Gopi | 34.35 |
| 33. | Gothra | 42.96 |
| 34. | Govindpura | 22.63 |
| 35. | Gudana | 20.87 |
| 36. | Hansawas Kalan | 27.54 |
| 37. | Hansawas Khurd | 19.09 |
| 38. | Hui | 22.16 |
| 39. | Jagrambass | 24.64 |
| 40. | Jawa | 20.07 |
| 41. | Jeetpura | 16.39 |
| 42. | Jewli | 38.10 |
| 43. | Jhojhu Kalan | 47.74 |
| 44. | Jhojhu Khurd | 41.95 |
| 45. | Kadma | 55.72 |
| 46. | Kakroli Hatti | 29.45 |
| 47. | Kakroli Hukmi | 48.92 |
| 48. | Kakroli Sardara | 31.18 |
| 49. | Kalali | 19.35 |
| 50. | Kaliyana | 16.22 |
| 51. | Kanhra | 34.60 |
| 52. | Kari Adu | 17.83 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------------|-------|
| 53. | Kari Dharni | 28.93 |
| 54. | Kari Mod | 26.40 |
| 55. | Kari Rupa Dass | 31.29 |
| 56. | Kari Tokha | 30.41 |
| 57. | Kheri Battar | 13.05 |
| 58. | Kheri Bura | 34.40 |
| 59. | Kheri Sanwal | 34.98 |
| 60. | Khorda | 30.57 |
| 61. | Kishkanda | 15.25 |
| 62. | Kubja Nagar | 13.98 |
| 63. | Lad | 21.05 |
| 64. | Ladawas | 28.59 |
| 65. | Mai Kalan | 19.66 |
| 66. | Mai Khurd | 22.54 |
| 67. | Makrana | 97.87 |
| 68. | Makraui | 66.27 |
| 69. | Mandhi Hariya | 26.77 |
| 70. | Mandhi Kehar | 22.22 |
| 71. | Mandhi Piranu | 19.80 |
| 72. | Mandola | 13.26 |
| 73. | Mandoli | 12.64 |
| 74. | Mehra | 17.31 |
| 75. | Mehrana | 17.06 |
| 76. | Mori | 33.25 |
| 77. | Nandha | 23.34 |
| 78. | Naurangabass Jattan | 10.55 |
| 79. | Naurangabass Rajputan | 12.72 |
| 80. | Nihalgarh | 13.17 |
| 81. | Nimar Badesara | 28.71 |
| 82. | Noswa | 45.08 |

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|------------------|----------------|
| 83. | Palri | 17.50 |
| 84. | Panchgoan | 17.58 |
| 85. | Patuwas | 22.63 |
| 86. | Pichopa Kalan | 73.26 |
| 87. | Pichopa Khurd | 31.32 |
| 88. | Ram Nagar Kapuri | 13.90 |
| 89. | Ramalwas | 13.88 |
| 90. | Rambass | 23.44 |
| 91. | Rehroda Kalan | 32.05 |
| 92. | Rehrodi | 20.56 |
| 93. | Rudroi | 28.36 |
| 94. | Santokhpura | 29.78 |
| 95. | Sishwala | 28.16 |
| 96. | Shyam Kalan | 25.34 |
| 97. | Sirsali | 9.95 |
| 98. | Surajgarh | 13.81 |
| 99. | Tikan Kalan | 23.18 |
| 100. | Todi Nagar | 23.31 |
| 101. | Umarwas | 28.63 |
| 102. | Unn | 15.17 |
| Total | | 2716.23 |

(बी) उपरोक्त गांवों में 2553 कार्यों हेतु सख्त राशि जारी की गई, जिसमें से 2095 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 326 प्रगति पर हैं तथा 132 कार्य अभी शुरू होने हैं।

Remains of Harappan Civilization at Rakhigarhi

589. Smt. Renuka Bishnoi: Will the Education Minister be pleased to state:

- (a) Whether it is a fact that the remains of the largest city of Harappan Civilization have been found during excavation at Rakhigarhi village in Hisar; if so the details of the findings thereof;

- (b) The steps being taken by the Government to develop Rakhigarhi as a magnificent site to attract national and international tourist; and
- (c) The further steps taken by the Government to carry out large scale excavation at the site in consultation with Archaeological Survey of India in order to find more artifacts relating to Harappan civilization?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल मातनहेल) :

(क) हां श्रीमान जी।

सिन्धु सभ्यता की चार बड़ी नगरीय सभ्यताओं (अन्यों में सम्मिलित हैं-

मोहनजोदड़ो हड़प्पा, पाकिस्तान और धौलावीरा, कच्छ गुजरात) में से राखीगढ़ी, जिला हिसार, हरियाणा एक है। गांव राखीगढ़ी जिला हिसार में स्थित चार टीलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन समारक 1996 में अधिसूचित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपरोक्त कुछ टीलों की खुदाई की गयी है। उत्खनन से प्राप्त पुरावस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ने अपने अधिकार में रखा हुआ है।

(ख) इस प्राचीन सांस्कृतिक स्थल पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्लान बजट वर्ष 2013-14 में 1.75 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा करवाया है। एक राज्य स्तरीय स्थल संग्रहालय एवं व्याख्यान केन्द्र गांव राखीगढ़ी में बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें हरियाणा के विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं को प्रदर्शित किया जायेगा। ग्राम पंचायत, राखीखास से इस उद्देश्य के लिए 5 एकड़, 2 कनाल, 10 मरला भूमि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा ली गई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय स्थल संग्रहालय एवं व्याख्यान केन्द्र की स्थापना हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सलाहकारों से इस वैचारिक प्रोजेक्ट में सहायता के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति का प्रकाशन मुख्य समाचार पत्रों में करवाया गया है और इसे अन्तिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने डक्कन कालेज, पुणे को राखीगढ़ी में उत्खनन कार्य करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

राखीगढ़ी में हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष

सिन्धु सभ्यता की चार बड़ी नगरीय सभ्यताओं (अन्यों में सम्मिलित है :- मोहनजोदड़ो हड़प्पा, पाकिस्तान और धौलावीरा, कच्छ गुजरात) में से राखीगढ़ी, जिला हिसार, हरियाणा एक है। गांव राखीगढ़ी जिला हिसार में स्थित चार टीलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन समारक 1996 में अधिसूचित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उपरोक्त कुछ टीलों की खुदाई की गयी है। उत्खनन से प्राप्त पुरावस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली ने अपने अधिकार में रखा हुआ है।

[श्रीमती गीता भुक्कल भातनहेल]

इस प्राचीन सांस्कृतिक स्थल पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के प्लान बजट वर्ष 2013-14 में 1.75 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा करवाया है। एक राज्य स्तरीय स्थल संग्रहालय एवं व्याख्यान केन्द्र गांव राखीगढी में बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसमें हरियाणा के विभिन्न हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त पुरावस्तुओं को प्रदर्शित किया जायेगा। ग्राम पंचायत, राखीखास से इस उद्देश्य के लिए 5 एकड़, 2 कनाल, 10 भरला भूमि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा ली गई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तरीय स्थल संग्रहालय एवं व्याख्यान केन्द्र की स्थापना हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सलाहकारों से इस वैचारिक प्रोजेक्ट में सहायता के लिए 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' का प्रकाशन मुख्य समाचार पत्रों में करवाया गया है और इसे अन्तिम रूप दिये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

Co-ordination of Welfare Schemes

576. Shri Sampat Singh: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop some mechanism to coordinate the social welfare schemes run by the various departments of the Government; if so, details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल भातनहेल) :

जी नहीं श्रीमान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं का समायोजन करने के लिए कुछ क्रियाविधि विकसित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विचाराधीन नहीं है।

One Stop Crises Centres for Women

590. Smt. Renuka Bishnoi: Will the Women and Child Development Minister be pleased to state :

- Whether it is a fact that the Government has decided to set up One Stop Crises Centres for Women at certain places in Haryana;
- if so, the salient features thereof; and
- The steps being taken by the Government to set up such centres in all the Districts and major towns all over Haryana for the benefit for women victims of domestic violence?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती गीता भुक्कल भातनहेल) :

- हां, सरकार ने फैसला किया है कि वन स्टॉप कारइसिज सेंटर प्रथम चरण में फरीदाबाद व गुड़गांव में स्थापित किए जाएंगे।

- (ख) इस सेंटर में एक ही छत के नीचे घरेलू हिंसा व दुराचार पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ अन्य सुविधाएं जैसे कि कानूनी सलाह, पुलिस सहायता, परामर्श/काउंसलिंग आदि सहायता दी जायेगी। हस्पताल का वरिष्ठ डॉक्टर जहां पर यह सेंटर स्थापित होगा संयोजक का कार्य करेगा। इस सेंटर में 8 से 10 व्यक्तियों की एक टीम होगी जिसमें एक परामर्शदाता, एक पुलिस अधिकारी, एक वकील, दो डॉक्टर ड्यूटी पे तैनात होंगे और अन्य सहायक स्टाफ जैसे नर्स, हैल्पर/सफाई कर्मचारी होंगे। यह सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा, जिसमें ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर व पुलिस अधिकारी हर समय तैनात रहेंगे। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह सेंटर उन शहरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 5 लाख या अधिक है।
- (ग) जिन शहरों की जनसंख्या 2 लाख या अधिक है वहां वन स्टॉप कारइसिज सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मुख्य मंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं संबंधी मामला उठाना/वॉक-आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने जबकि बजट पेश होना है, बजट पेश होने से पहले हाउस के बाहर घोषणाएं की हैं जोकि परंपराओं के टोटल खिलाफ है। इस तरह के कार्य से हाउस की अवमानना हुई है (शोर एवं विघ्न) अब जबकि घोषणायें बजट प्रस्तुत होने से पहले ही कर दी गई हैं तो ऐसे में बजट पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। (शोर एवं विघ्न) यह तो सिर्फ फारमैलिटी पूरा करने का ही काम किया जा रहा है। (शोर एवं विघ्न)

Sh. Anil Vij : Speaker Sir, it is clearly mentioned in Kaul and Shakhdar that as and when the House is in Session, no announcement can be made outside the House. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जब सारी घोषणायें तो हाउस के बाहर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर कर दी जाती हैं तो ऐसी स्थिति में बजट पढ़ने का क्या औचित्य रह गया है? (शोर एवं विघ्न) जो घोषणायें होती हैं उन्हें इस हाउस के अन्दर बजट के माध्यम से ही करना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Leader of the House is making a statement. Please sit down. (Interruption) Please sit down.

मुख्यमंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी यह बलायें कि मैंने कौन सी घोषणा सदन के बाहर की है? गवर्नर के रिप्लाय में जो बातें हाउस के अन्दर कहीं गई हैं वहीं बातें मैंने हाउस के बाहर कही हैं। (शोर एवं व्यवधान) हाउस के अन्दर ही सारी बातें कही गई हैं (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I don't take any cognizance about it. (Noise & interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मुख्यमंत्री महोदय ने हाउस के बाहर बैठ में छूट करके तथा आर्टों रिक्शा चालकों को टैक्स में छूट दी। क्या ये सभी बातें बजट में नहीं आ सकती थी? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, यह सभी बातें हाउस के अन्दर ही कही गई थी। It is on record. (Noise & Interruption)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, आटो रिकशा के बारे में यदि हाउस में न कहा हो, तो हाउस की प्रोसिडिंग्स निकालकर देख लो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल, यह सभी बातें हाउस के अन्दर ही कही गई थी। May be he was not listening at that time. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, सारी घोषणाएँ हाउस के बाहर की गई हैं। अगर बजट आज प्रस्तुत होना था तो क्यों बजट प्रस्तुत होने से पहले हाउस के बाहर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर घोषणाएँ कर दी गई हैं? इस प्रकार से अब बजट प्रस्तुत करने का औचित्य बिल्कुल समाप्त हो गया है? (विघ्न)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल) : स्पीकर सर, मैं भी इस बात का गवाह हूँ, कि ऑटो व रेहड़ी से संबंधित टैक्स में छूट करने संबंधी सभी प्रकार की बातें हाउस के अन्दर ही की गई हैं। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर की रिप्लाय में मैंने यह सब बातें हाउस के अन्दर कही हैं। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी इस हाउस के एक सीनियर मेंबर हैं। मैं उनसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकता था। अरोड़ा जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, ऑटो स्कूटर और रेहड़ी से संबंधित टैक्स में छूट करने की घोषणाएँ संबंधी बातें हाउस में ही हुई हैं। (शोर एवं व्यवधान) don't recognize this objection. (Noise & Interruption) It is a frivolous objection. (Noise & Interruption) Please sit down. (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जो घोषणाएँ सदन के बाहर कैबिनेट मीटिंग बुलाकर की गई हैं इनको बजट में प्रस्तुत किया जा सकता था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : स्पीकर सर, जब मैंने सदन में यह घोषणाएँ की थी तो उस समय अरोड़ा साहब सदन में मौजूद नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : स्पीकर सर, विपक्ष के साथी तो सदन में सोते रहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. I am not recognizing this.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि हमारे विपक्ष के साथी आटो थालों के बिल्कुल खिलाफ हैं (शोर एवं व्यवधान)

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, विपक्ष के साथी विज साहब का बर्ताव तो देखिये वे इस मर्यादित सदन में छाती पीट रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा) : स्पीकर सर, कल विपक्ष ने शांति और अमन से सदन में व्यवहार करने का वायदा किया था। (शोर एवं व्यवधान) उसी वायदे के मुताबिक इनकी सस्पेंशन को रीलिज किया गया था। (शोर एवं व्यवधान) लेकिन आज विपक्ष ने उस वायदे को एक बार फिर से तोड़ दिया है (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के दूसरे सदस्यों से तो इस प्रकार के अमर्यादित व्यवहार की उम्मीद थी लेकिन अरोड़ा जी कम से कम आपसे तो इस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद कलाई नहीं थी? (शोर एवं व्यवधान) आपको सदन में आराम से बैठकर बात करनी चाहिए और सुननी चाहिए (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार भादली : स्पीकर सर, विपक्ष के साथी सदन में इस प्रकार का अमर्यादित व्यवहार करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, जब हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही है तो हम विरोध स्वरूप सदन से वाक आउट करते हैं।

उद्योग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : स्पीकर सर, हमारे विपक्ष के साथी आज फिर बहाना बनाकर सदन से वाक आउट कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage, all the Members of the Indian National Lok Dal and a member of the Shiromani Akali Dal present in the House staged a walk out as a protest against the major announcements made by the Chief Minister outside the House at a time, when the Assembly was in Session.)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Mr. Vij, third time you are interrupting this House. (Interruption) The Hon'ble Finance Minister is on his leg (Interruption) Please sit down (Interruption) I have ruled it out. (Interruption)

श्री अनिल विज : ठीक है सर, यदि हमारी बात को सुना ही नहीं जायेगा तो हम भी सदन से वाक आउट करते हैं।

(At this stage, all the Members of the Bhartiya Janata Party present in the House staged a walk out as a protest against the major announcements made by the Chief Minister outside the House at a time, when the Assembly was in Session.)

अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(i)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Smt. Geeta Bhukkal Matanhail, Education Minister in which she has expressed her inability to attend the sitting of the House today, the 28th February, 2014 due to unavoidable circumstances.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Shiv Charan Lal Sharma, Minister of State for Labour and Employment in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 28th February, 2014 due to his ill-health.

(iii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Rao Dan Singh, C.P.S./Town & Country Planning and Education in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 28th February, 2014.

(iv)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Rao Dharam Pal, MLA in which he has expressed his inability to attend the sitting of the House today, the 28th February, 2014 due to his ill-health.

वर्ष 2014-2015 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Finance Minister will present the Budget estimates for the year 2014-2015 (इस समय मेजें थपथपाई गई)

Finance Minister (Sardar Harmohinder Singh Chattha) : Hon'ble Speaker Sir,

I rise before this august House to present the budget estimates for the year 2014-15. I express my gratitude to this House for giving me an opportunity to

present the third consecutive budget for the State. Remarkable progress on all fronts has been made by this Government in the last over four years under the able leadership of Shri Bhupinder Singh Hooda, Chief Minister, Haryana and with the whole-hearted support of the Central Government. All segments of the society have greatly benefitted by the rapid pace of economic growth achieved through the progressive and people-friendly policies of the Government. The people of Haryana have witnessed an unprecedented era of peace, social harmony, freedom and all rounded growth.

2. As a result of the forward looking policies of our Government, all macro-economic indicators have shown greater improvement than the national averages. I will explain this matter in more details shortly. The hard working farming community of the State has been delivering record foodgrains and agriculture production. Record number of universities, colleges, schools, medical colleges, hospitals, other health and technical education institutions have been set up or upgraded for providing quality education and healthcare to the people of Haryana. Infrastructure like power plants, sub-stations, transmission and distribution systems have been vastly expanded, strengthened and upgraded. Huge network of irrigation system, road network and drinking water system have been created, strengthened and improved with massive investments. Liberal policies have been adopted for the welfare of weaker sections of society including increase of pension for old age persons, widows, handicapped persons etc. Numerous schemes have been launched for the benefit of the persons belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, and BPL families. All group C and D employees have been granted interim relief @ ₹ 2000 per month, and Haryana Police Constabulary has been granted Risk Allowance @ ₹ 5000 per month with effect from 01-01-2014. People of the State have already started getting benefitted by the policies of the Government. Our Government headed by the Chief Minister, Shri Bhupinder Singh Hooda, derives great satisfaction for having discharged its duties towards the people of Haryana sincerely, honestly and efficiently.

3. Speaker Sir and Hon'ble Members, the progress made so far is naturally giving rise to further increase in expectations of the people. The improved quality of life is fuelling the needs and expectations for further improvement. This naturally is posing bigger challenges for the Government. Increased rate of urbanization is a universal phenomenon in all developing societies. The rapid rate of economic growth of Haryana is giving rise to ever increasing rate of urbanization of the State. Urban population of Haryana has increased from 31 percent in the year 2005-06 to about 35 percent in the year 2013-14. Urbanization means greater opportunities in terms of more jobs for the youth and also more choices for leading better quality of life. It also means huge challenge for the Government in terms of providing urban amenities, water and electricity supply and efficient system of local self governance.

4. Sir, our Government has served the people well and with best of intentions. We are certain that people will continue to repose their faith in this Government and give us another opportunity for continuing this noble task after the election

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

of the next Vidhan Sabha scheduled to be held in October, 2014. Our track record shows that we fulfill what we promise.

5. Sir, we promise more inclusive, faster and sustainable growth of all segments of society; we promise an efficient, transparent and honest Government; we promise jobs and employment opportunities for our youth; we promise good care of the weaker sections to provide them equal opportunities for progress; we promise ultra modern agricultural practices for our farmers; we promise efficient operation of infrastructure including power, roads, water supply, sewerage system, drainage system etc., we promise best of health and educational facilities in all the districts of the State; we promise ultra modern industrial complexes to leverage economic opportunities of the future and above all, we promise a fully empowered decentralized local self Government.

6. Sir, with these solemn assurances, I present before this House broad macro-economic indicators as well as a gist of the budgetary allocations proposed for major departments of the Government.

Macro Economic Indicators

7. The Gross State Domestic Products (GSDP) of Haryana continues to grow at a pace much faster than the GDP of the country. It is estimated that during the 11th Five Year Plan period i.e. 2007-2012, the State economy registered an average growth of 8.7% compared with national average growth of 8%. According to the estimates prepared by Central Statistical Office, GDP of the country grew @ 4.5% in the year 2012-13 and is estimated to grow @ 4.9% in 2013-14. It has been estimated by Department of Economic & Statistical Analysis, Haryana that the economy of Haryana will grow at the rate 2% more than the national average growth i.e. 6.5% in the year 2012-13, and 6.9% in the year 2013-14. This is a great achievement which reflects upon robustness of the economy and resilience of the hard working people of Haryana.

8. The Gross State Domestic Product of Haryana at current prices for 2013-14 is estimated to be ₹ 3,92,894.05 crore compared with that of ₹ 2,23,600.25 crore in the year 2009-10. At constant prices, with base year prices of 2004-05, the GSDP of Haryana increased from ₹ 1,52,474.47 crore in 2009-10 to estimated ₹ 2,01,077.08 crore in the year 2013-14.

9. In tune with the above figures of GSDP, per capita income at current prices increased from ₹ 82037 in 2009-10 to ₹ 1,35,007 in the year 2013-14, and at constant prices it increased from ₹ 55044 to ₹ 68040 during the same period. The per capita income of Haryana is highest in the country amongst large States. Only two small States, Goa and Sikkim, have per capita income higher than Haryana.

10. Structure of the economy of the State also continues to show constant progress. Greater percentage of secondary and tertiary sectors of economy represents greater progress and development. The primary, secondary and tertiary

sectors contributed 17.3 percent, 30 percent and 52.7 percent to the GSDP of the State in the year 2009-10, which at present stands at 15.1 percent, 26.9 percent, and 58 percent. Greater contribution of the manufacturing and service sectors means the population of the State is getting more educated, more investments are taking place, and more job opportunities are available for the youth.

11. High rate of inflation, high interest rates, pressure on rupee are impacting the overall economy of the country as well as that of Haryana. For these reasons, relatively lesser investments are taking place. I hope and expect that in the near future the rate of growth of the economy will improve which will directly benefit trade, industry and commerce in Haryana, which in turn will yield greater revenues for the state. I am quite hopeful of economic turnaround of the country which will give further boost to the economy of Haryana.

12. Total revenue receipts (TRR), according to the revised estimates (RE) 2013-14 are expected to be ₹ 41635.94 crore comprising States own tax revenue (SOTR) of ₹ 30234.52 crore and non-tax revenue of 11401.42 crore. As per budget estimates (BE) 2014-15, TRR is projected to be 47690.14 crore of which SOTR is estimated to be 34384.71 crore and non tax revenue at 3305.43 crore, registering a growth of 14.54 percent. The revenue expenditure for RE 2013-14 is projected to be ₹ 47248.86 crore and for BE 2014-15 is estimated to be 52702.71 crore, out of which estimated expenditure on Salaries is 14736.52 crore, on Pensions 4500 crore, and on interest payments it would be 7138.89 crore. The revenue deficit as per RE 2013-14 is 5612.92 crore whereas in BE 2014-15 the revenue deficit will be 5012.57 crore. The fiscal deficit as per RE 2013-14 is 11515.61 crore whereas for BE 2014-15 it is ₹11393.29 crore.

13. I am proposing an overall outlay of ₹32731.29 crore for Annual Plan 2014-15, compared with ₹24182.42 crore proposed for RE 2013-14. This outlay includes an amount of ₹10158.80 crore of state public sector enterprises (PSEs) and 1052.34 crore of local bodies to be met from their own resources. After excluding the outlay of PSEs and local bodies, the net state plan outlay for the year 2014-15 is proposed at ₹ 21520.15 crore, including central assistance.

14. As per Haryana FRBM Act, 2005, we are committed to eliminate revenue deficit and contain fiscal deficit within three percent of gross state domestic product. As a result of the good fiscal management, the fiscal deficit was 3 percent in 2012-13 and 2.93 percent in RE 2013-14 and it is projected to be 2.54 percent in BE 2014-15. The revenue deficit as percentage of GSDP in the year 2012-13 was 1.29, in 2013-14, 1.43 and it is projected to be 1.12 in 2014-15. We are trying to completely eliminate revenue deficit. We could have become revenue surplus State had the due arrears of Central Sale Tax compensation been received during 2013-14 from the Central Government. The long halted mining activities are likely to commence in the State in the year 2014-15; and with further administrative steps being taken, like implementation of e-Taxation project, there would be substantial additional resource mobilization which will help eliminate the existing revenue deficit which as per FRBM Act, 2005 should be zero percent.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

15. As per recommendations of the Thirteenth Finance Commission, the net borrowing limit of the State has been fixed as three percent of GSDP. However, during 2011-12 and 2012-13 the actual borrowing was ₹6184.81 crore and ₹8700.87 crore respectively against the available borrowing limit of ₹8162 crore and ₹10115 crore respectively. We are consciously borrowing less than the available limit with a purpose to reduce interest burden on the State exchequer.

16. The permissible limit of debt to GSDP ratio under the FRBM Act, 2005 is 22.7 percent for 2012-13, 22.8 percent for 2013-14 and 22.9 percent for 2014-15. Against these our debt to GSDP ratio was 17.43 percent in 2012-13, 17.91 percent in RE 2013-14, and 18.24 percent in BE 2014-15. It shows that the State is well within the sustainable debt limit.

Industries and Commerce Department

17. Hon'ble Members, our state continues to retain its position as a preferred investment destination. Exports from the state have increased from ₹ 54,991 crore during 2011-12 to ₹ 59,806 crore during 2012-13 registering an increase of more than 8 percent.

18. Haryana had declared 2013 as the 'Year of Industry and Employment'. Recognizing that the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) constitute backbone of the manufacturing sector, the government has adopted the strategy of establishment of common facility centres (CFCs) in public-private-partnership (PPP) mode under the Cluster Development Scheme. A total of 29 such clusters have been identified. These clusters would address common needs of MSMEs in the areas of research and development, technology up-gradation, standardization of products etc.

19. We are also taking steps to create a sizeable pool of technical and skilled manpower through the establishment of a number of institutes. Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Govt. of India has sanctioned two projects of tool room and technology centres at IMT, Rohtak and at Industrial Growth Centre, Saha with an investment of more than ₹100 crore in each of these projects. Each technology centre is expected to train about 10,000 trainees every year through various long-term and short-term training programmes.

20. The industrial infrastructure is being strengthened in the state through development of new industrial model townships, industrial parks, and expansion of the existing industrial estates. Industrial model townships (IMTs) are being developed at Faridabad, Rohtak, and Roj-ka-Meo in Mewat. In addition to a new industrial estate at Panipat, further expansion has been undertaken for a number of existing projects including IMT Manesar, IMT Bawal, Industrial Estate Kundli, Phase III of Industrial Estate Barbi, and Industrial Estates at Karnal, Barwala and Phase-II of Manakpur. About 3200 acres of land has been acquired for development of an industrial model township at Kharkhauda. HSIIDC has already incurred an expenditure of ₹1802 Crore till December 2013 on land acquisition and development

works. E-Biz portal has been started for integration of services from government to business (G2B) community for the ease of starting and doing business and dealing with permits and licenses across the business life cycle. HSIIDC is also in the process of implementing projects on labour housing, flatted factories and skill development.

Power

21. Power is one of the most important infrastructures for the State. Unprecedented growth and development in this sector has taken place in the last four years. I am very proud to say that the state owned generation capacity has increased from 2085.5 MW in 2009-10 to 5300.05 MW up to January, 2014. The total generation capacity of the State, including the joint, central and other generating projects, has reached 10277 MW compared with 4639 MW in 2009-10. Apart from the generation capacity, the number of sub-stations of 33 KV to 400 KV capacities has increased by 229 in last 4 years. The length of transmission and distribution lines has increased by 3381 kilometers. As a result of these efforts, average supply of 1205 lakh units per day is being made in the State at present compared with 867 lakh units per day in the year 2009-10.

22. Various power utilities have further planned to make additional investment of ₹3991 crore in the year 2014-15. This investment will be made with the help of ₹850 crore as proposed Plan allocation in the budget estimates of 2014-15, and ₹3141 crore by way of loans from various institutions. Besides, ₹4500 crore are proposed to be earmarked on non plan side for the year 2014-15 for the Power department.

Irrigation

23. Haryana gets its share in various rivers as per respective inter-state agreements. Despite less availability of water resources the State has been managing its available surface water resources efficiently, due to which the State has become one of the main contributors to the national basket of food grains. In order to improve availability of water in Yamuna River during lean season, Haryana has been actively pursuing upstream storage dams. The work of Lakhwar and Vyasi projects is expected to begin in near future. Environmental and other clearances of Renuka and Kishau projects are being pursued actively.

24. The State has an extensive network of 1505 canals, with a length of 14490 kms; 15404 watercourses; and a vast network of 800 drains. The canals and drainage network of the State is old, therefore, rehabilitation of the same has become very important for ensuring conservation and efficient management of the available surface water. During the current year, Irrigation department carried out rehabilitation of 51 channels at a cost of about ₹ 102 crore.

25. Work of remodeling and rehabilitation of watercourses, which were lined long back, have also been taken up in a phased manner. 2697 watercourses have been rehabilitated so far out of the identified 7500 such watercourses. During the year 2013-14, ₹ 104 crore were spent for this purpose.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

26. Many irrigation works have been completed and many have been taken up during this financial year. With the functioning of Bhiwani-Ghaggar drain and Smain Dhanana link drain; the problem of drainage of floodwater in the areas served by these drains has been addressed. The work of Nalwa distributary costing ₹ 30 crore is nearing completion. It will provide drinking and irrigation water to 12 villages of Hisar and Bhiwani districts. The problem of storm water drains of Panipat and Faridabad had been engaging attention of the Government. I am happy to inform that the Government has recently approved cleaning and concrete-lining of Panipat drain costing ₹45 crore, and Gaunchi drain costing ₹ 14 crore. This will provide much awaited relief to the people of these towns. Further, the work of increasing the capacity of Rangoi Nalla by way of deepening has also been started at a cost of ₹17 crore. During this financial year works of Ratta Khara and Nai Walla Kharif Channels in Sirsa districts have been started at a cost of ₹72 crore and ₹55 crore respectively.

27. During 2013, an all time high discharge of more than 8 lakh cusecs was recorded at the Hathni Kund Barrage. The flood water caused some damages and erosion of land along the river but the damage was contained due to the flood works executed in recent years. During the current financial year, 54 schemes of flood control and drainage works have been completed. Besides, work on 84 schemes is under progress. Total expenditure on flood works would be more than ₹110 crore during the financial year 2013-14.

28. I propose to allocate ₹1009.59 crore for this sector during 2014-15 on plan side and ₹ 1200.16 crore on non plan side.

Agriculture

29. The landmark achievements made by hard working farmers of the State in making Haryana as one of the most agriculturally advanced State in the country are known to everyone. I salute the farmers of the State for helping make India a food surplus country. Agriculture is backbone of the economy of the State as majority of the population continues to be directly or indirectly dependent upon agriculture and allied activities. Our Government fully realizes its responsibilities towards this vital sector of the economy. Haryana achieved an all time high food production of 183.42 lakh metric tonne in the year 2011-12. The food grain production of the state was 130.57 lakh metric tonne in the year 2004-05 and 153.46 lakh metric tonne in the year 2009-10. For the current year the targeted food grain production is 180.15 lakh metric tonne which we expect to surpass. Sir, the efforts made by Haryana Government and the hard work exhibited by the farmers have been duly recognized at the national level as 'Krishi Karman Award' has been conferred upon the State twice and for the year 2012-13 'Commendation Award' has been given for sustained high productivity in wheat and rice. Agriculture sector is being fully supported by the State by ensuring timely availability of quality seeds, fertilizers, pesticides and other inputs at highly subsidized rates. The consumption of chemical fertilizer is likely to touch 14 lakh

MT (nutrients) during the year 2013-14. Gypsum is being provided to the farmers on 50 percent subsidy. Irrigation systems are being modernized at rapid pace by encouraging installation of sprinkler sets, underground pipe-line system, drip irrigation system etc. Timely advice is being given to the farmers through a network of technical staff, offices and laboratories. Under a major initiative of Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY) launched by the Government of India, 4% rate of growth of agriculture has been aimed for the year 2013-14. I am happy to note that the State Government has fixed State Advisory Prices (SAP) for sugar-cane at ₹301/-, ₹295/- and ₹290/- per quintal for late, mid and early varieties for the crushing season 2014-15, which is a record high price given to the farmers. Three sugar mills, namely, Shahabad, Karnal and Panipat have won national level awards for technical efficiency and cane development.

30. For continuing the pace of progress in agriculture sector, I propose to earmark ₹ 630.06 crore on the plan and ₹ 300.37 crore on the non plan side for the agriculture department in the budget estimates of the year 2014-15.

Horticulture

31. Haryana Government is relentlessly pursuing the objective of crop diversification, as a result of which 6.71 percent of the gross cropped area representing 4.38 lakh hectares has come under horticulture crops. 83 percent area out of this is under vegetables. Haryana has attained a pre-eminent position in mushroom production. Several initiatives have been taken for bringing additional area under horticulture and for introduction of modern technologies. Assistance in the form of subsidies for setting up of poly houses has been increased from 50 percent to 65 percent. 85 percent assistance is being given to small and marginal farmers and 75 percent to other farmers for installing micro irrigation systems. Construction of water storage tanks is being encouraged on 100 percent assistance basis. Projects have been initiated for encouraging cultivation of guava, banana and papaya. The centres of excellence established at Gharaunda for vegetables and at Sirsa for fruits are having major demonstrative effect on the farmers. For the year 2014-15, I propose to earmark ₹ 22.07 crore on non-plan side and ₹ 294.48 crore on plan side for this sector including the central share.

Animal Husbandry

32. Quality veterinary care and breeding services are being provided for over 90 lakh livestock population of the State through 2799 veterinary institutions. Special attention is being given to further improvement of genetic material of livestock through conservation, multiplication and improvement of indigenous germ-plasm such as Murrah breed of buffaloes, and Haryana and Sahiwal breeds of cows. Per capita per day milk availability in the State is 747 grams as compared to the national average of 285 grams. A new scheme named "Mukhyamantri Gramin Dudharu Pashudhan Suraksha Yojna" has been launched in the state with effect from 1st January, 2014. Under this scheme there is a provision of compensation ranging from ₹ 20,000 to ₹ 50,000 in the case of cows and buffaloes, and ₹ 3000 in

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

case of goats, to the owner of the animal in the eventuality of untimely death of the registered milch animal. For enhancing production of livestock products and overall growth of this sector, the government has decided to set up a "State Livestock Mission" in the State.

33. For encouraging milk producers, a scheme named "Mukhya Mantri Dugdh Protsahan Yojana" was launched this year, under which a subsidy @ ₹ 4 per litre was given to the milk producers of Haryana State supplying milk to District Cooperative Milk Unions during the period 27th June, 2013 to 30th September, 2013. It has also been decided to continue this scheme from April to September during the next two years. I propose to earmark ₹ 421.77 crore on the non plan side and ₹ 154.30 crore on the plan side for this sector in the financial year 2014-15.

Fisheries

34. Haryana has achieved a rapid progress in the field of fish production. It is targeted that the fish production would be raised from 1,20,000 MT in the year 2013-14 to 1,30,000 MT by the end of 2014-15. Fish productivity has been aimed to be raised from 5800 to 5900 kilograms per hectare per year. The water area under the fish culture would be raised from 20,200 hectares at present to over 22,000 hectares by the end of 2014-15.

Town & Country Planning

35. Haryana surrounds the national capital New Delhi on three sides. Taking full advantage of its location, an economically vibrant environment has been created in the areas around Delhi. The growth and development of Gurgaon, Faridabad, Jhajjar and Sonapat districts is known to all. The metro extension from Delhi to Gurgaon linking City Centre, Sector 29, Gurgaon with Delhi is functional since September, 2010. The Delhi metro is now being extended to YMCA chowk Faridabad and further to Ballabgarh. The project up to YMCA chowk is likely to become operational by September, 2014. The work of extension of the metro from Mundka in Delhi to Bahadurgarh is also in progress and likely to be completed by March, 2016. High speed metro rail connectivity between Indira Gandhi International Airport and IFFCO Chowk, Gurgaon is also being envisaged. Similarly, metro link between Delhi and Kundli in district Sonapat via Narela is being envisaged. The Regional Rapid Transit System (RRTS) for 8 corridors of the National Capital Region (NCR), four of which fall in Haryana sub region of NCR, is being developed. These corridors have been approved in principle by the Government of India and the Government of Haryana. Sir, with these projects, not only the NCR region of Haryana but also the entire State will be highly benefitted by way of providing investment opportunities to the entrepreneurs and employment opportunities to the youth.

36. I am happy to note that in addition to the existing Haryana sub region of NCR comprised of Panipat, Sonapat, Jhajjar, Rohtak, Gurgaon, Faridabad, Rewari, Palwal and Mewat districts, it has been decided to include Bhiwani, Mahendragarh,

Jind and Karnal districts also in the National Capital Region. This will surely prove a boon for the State.

Housing

37. Dwelling house is a fundamental need of every human being. Ambitious programmes have been launched to ensure that every family has a roof over its head. With this objective in mind Mahatma Gandhi Gramin Basti Yojna was launched in the year 2008 under which free residential plots of 100 Square yard are being allotted to eligible Scheduled Caste, Backward Class-A and BPL families. Up to December, 2013, 3.55 lakh families have been conferred ownership rights on the plots. Distribution of plots to remaining eligible families is in progress.

38. In June, 2013 a new affordable housing scheme named 'Priyadarshni Awas Yojana' for rural poor persons was launched, under which it is aimed to provide financial assistance to 2 lakh families for construction of houses within two years i.e. 2013-14 and 2014-15 at a cost of ₹1350 crore.

39. Initially those families were eligible who either were on permanent wait list of 'Indira Awas Yojna' (IAY) or who had no house or had only a katcha house. I am glad to say that recently this scheme has been extended in scope by including those IAY beneficiaries, or the beneficiaries under any other scheme to whom assistance was provided prior to April, 2008 and whose houses are in dilapidated and inhospitable condition. It has also been extended to those persons who have inadequate housing facility with less than 20 Square meter covered area. About 1.06 lakh beneficiaries have already been registered under this scheme. First installment of the assistance has been released to 78,000 families and second installment to 36662 families. The Government has also coordinated with several banks for providing loans to the beneficiaries' up to ₹1 lakh on low rate of interest.

40. I am happy to state that the Housing Board Haryana has initiated a massive programme for the construction of EWS houses for the BPL families in the State of Haryana. The Housing Board has planned to construct 50,000 houses, out of which work on 32,000 houses has already started and the balance work is likely to be taken up during the next financial year. It is pertinent to mention that these houses are of 300 Square feet covered area. Payment terms for the allottees are very reasonable. They have to make payment in easy installments in 13 years. The Housing Board has arranged loan from HUDCO for this purpose. The total cost of the project is likely to be over ₹ 2250 crore. Land for these houses has been provided by HUDA and Town and Country Planning Department at nominal rates.

Urban Local Bodies

41. Being a progressive State, urban population of Haryana is increasing rapidly and its cities are growing at a fast pace. It is estimated that at present nearly 35 percent of the population of the State lives in urban areas. Increased emphasis is being laid on strengthening of urban infrastructure. Several new infrastructural projects under Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission (JNNURM) have been submitted to the Government of India including

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

strengthening of road network and sewerage system in Faridabad city. Five pilot projects under Rajiv Awas Yojana for slum development in the towns of Ambala, Yamuna Nagar, Rohtak, Hisar and Sirsa have been approved by the Government of India. For the welfare of small shopkeepers in the cities, a new scheme has been launched to compensate them up to an amount of ₹ 5 lakh in the case of loss of their commercial property due to fire, floods or other natural calamities. Schemes have also been introduced for up-gradation of chaupals and community centres in municipal areas. Street vendors are an integral part of our social and economic system. For protection of their livelihoods and to avoid their harassment, "The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Ordinance, 2013" has been promulgated. A package of relief for auto rickshaw owners is proposed to be prepared including the facility of paying one time road tax and passenger tax; compensation in the event of damage to the auto rickshaw; and covering the owners under 'Rashtriya Swasthya Bima Yojana'.

42. I propose an allocation of ₹1935.32 crore under plan and ₹135.31 crore under non plan for the Urban Local Bodies department in the financial year 2014-15.

Development & Panchayats

43. Several programmes are being implemented for improving living conditions in our villages including 'Mukhya Mantri Anusuchit Jaati Nirmal Basti Yojna'; 'Nirmal Bharat Abhiyan' etc. Large numbers of programmes are being implemented through Haryana Rural Development Fund (HRDF). For improving financial position of Panchayats, a surcharge of 5 percent on VAT collected by Excise and Taxation Department was imposed in the year 2010-11, which is distributed amongst Urban Local Bodies and Panchayati Raj Institutions (PRIs) in the ratio of 80:20. An amount of about ₹156.54 crore was released during the current year under above scheme and an amount of ₹179.38 crore has been earmarked for this purpose for the year 2014-15 for PRIs. Overall outlay for the Development and Panchayat Department is proposed to be ₹ 611.19 crore on the non-plan and ₹ 1699.18 crore on the plan side in the financial year 2014-15.

Police

44. One of the important reasons for the all round growth of the State is its excellent law and order condition. Haryana is a preferred destination of industrialists and entrepreneurs for this reason also. Great emphasis has been laid on modernization of Police department. For expeditious recruitment of police personnel, Haryana Police Recruitment Board has been constituted. Coordinated action is being taken for modernization of police stations and for construction of houses for the constabulary and officers. Keeping in view the arduous and risky nature of duties being performed by the Haryana police constabulary, it has been decided to grant risk allowance to them @ ₹5000/- per month. A provision of ₹ 3136.35 crore under the non-plan and ₹ 138.01 crore under the plan heads has been proposed for the Police, Jails and Judicial departments for the year 2014-15.

Roads and Bridges

45. Highways and railways are lifelines of the economy of the country and the state. The PWD (B & R) manages a total roads network of 27084 km, out of which 426 km are national highways, 2422 km are state highways, 1471 km are major district roads, and 21625 km. are other district roads. Besides their maintenance, upgradation and strengthening, wherever required, our Government took up the construction of ROBs on a large scale all over the state. From 1966 to 2005 only 16 ROBs were constructed, whereas 41 ROBs and 1 RUB have been constructed at a cost of ₹ 1149 crore during the period from 2005 to January, 2014. Construction of another 31 ROBs costing ₹ 952 crore is in progress.

46. In addition, the State Government has actively pursued the upgradation of various National Highways under the National Highways Development Programme. At present projects worth about ₹ 3300 crore have been completed, while works of about ₹ 5800 crore are in progress and of ₹ 4500 crore are in the pipeline. A prominent project for the 4-laning of Panipat-Gohana-Rohtak-Jhajjar-Bawal costing about ₹ 1457 crore and covering 165 km. has been completed. In addition, Rohtak-Jind-Narwana-Punjab border highway is also being 4-laned at a cost of about ₹ 725 crore which shall cover a length of 118 km. Similarly, Rohtak-Hisar highway shall be 4-laned at a cost of ₹ 959 crore covering a length of 99 km. For 4-laning of Ambala-Kaithal road, tenders have been invited for a length of 95 km costing about ₹ 1100 crore.

47. The construction and rehabilitation has been taken up on a large scale. Since 2005, 124 bridges have been completed at a cost of ₹ 209 crore, while 26 bridges are in progress with a cost of ₹ 88 crore, and 28 more bridges at a cost of ₹ 124 crore are to be taken up.

48. During the year 2013-14, an expenditure of ₹ 1823 crore under various schemes has been incurred and 2672 kilometer of road length repaired up to 30th November, 2013. In addition, works amounting to ₹ 4438 crore involving improvement and construction of roads have been taken in hand.

49. Haryana is one of the few states that have qualified for PMGSY-II. The empowered committee of the Ministry of Rural Development, Government of India, has approved proposals for strengthening and upgradation of rural roads covering a length of 1010 km. including 18 bridges, costing about ₹ 960 crore. The execution of works is expected to start by April, 2014.

50. The work of Rewari-Jhajjar-Rohtak railway line covering a length of 81.257 km. has been completed at a cost of ₹ 603 crore. The work on Jind-Sonepat-Gohana railway line covering a length of 80.75 km. is likely to be completed at a cost of ₹ 693 crore by March 2015. The Rohtak-Meham-Hansi Railway line with a total length of 70 km. is also being taken up at a cost of ₹ 405 crore.

Public Health Engineering

51. Government is striving hard to ensure adequate water supply in all the villages as well as urban areas. Plan budget of the department is used for

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

augmenting water supply in those villages where the supply level falls below 40 litres per capita per day due to any reason. Similarly the water distribution system is further augmented and expanded from time to time to ensure that 100 percent population is covered. Under such schemes, 861 habitations were identified for augmentation of water supply out of which 410 habitations have already been covered and the remaining will be covered before 31st March, 2014. Another 850 habitations have been targeted for coverage in the year 2014-15. Similarly, it is being ensured that 135 litre per capita per day water is supplied in all the urban areas. 166 schemes for providing sewerage system in the towns of the State are also in progress. Installation of sewage treatment plants in the towns of the Haryana will prevent pollution of surface water bodies and also provide clean environment to the residents.

52. For the year 2014-15, I propose to earmark ₹ 1096 crore on plan side and ₹ 1332 crore on non plan side for Public Health Engineering Department.

Revenue & Disaster Management

53. For taking revenue administration to the door steps of the people, in the last 5 year's 13 new Sub Divisions and 23 Tehsils/Sub Tehsils have been created. The remuneration of village chowkidar has been increased from ₹ 2500 to ₹ 3500 and of lambardar from ₹ 1100 to ₹ 1500 per month. This will benefit about 24000 lambardar and 7017 chowkidar in the State. Our Government is also ensuring that sufficient funds remain available all the time for any unforeseen event of natural calamity requiring providing of relief to the public. Whenever any damage on account of natural calamities occurs, prompt relief is provided to the people.

54. Government has enhanced the rates of relief in the event of damage to standing wheat, paddy and cotton crops due to flood, fire, electric sparking, hailstorm and dust storm etc. from ₹ 5500 to ₹ 10000, ₹ 4500 to ₹ 7500, ₹ 3500 to ₹ 5000 for damages between 76 percent to 100 percent, 51 percent to 75 percent and 26 percent to 50 percent respectively. Similarly the rates of relief on account of damage to other standing crops due to flood, fire, electric sparking, hailstorm and dust storm have been increased from ₹ 4500 to ₹ 7500, ₹ 3500 to ₹ 5000, ₹ 2500 to ₹ 4000 for damages between 76 percent to 100 percent, 51 percent to 75 percent and 26 percent to 50 percent, respectively.

55. The rates of relief on account of damage to standing wheat, paddy and cotton crops due to drought have been increased from ₹ 2700 to ₹ 4000 for 51 percent and above damage. Similarly, the rates of relief on account of damage to other standing crops due to drought have been increased from ₹ 2100 to ₹ 3500 for 51 percent and above damage.

56. Besides the Disaster Response Fund, which at present stands at about ₹ 1400 crore, I propose to earmark ₹ 661.34 crore on the non plan side and ₹ 11.57 crore on the plan side for the Revenue and Disaster Management department in the financial year 2014-15.

Social Justice & Empowerment

57. Haryana government is fully committed to the welfare of vulnerable sections of society. It is the responsibility of the State to take due care of aged persons, widows, destitute women, disabled persons and other weaker sections. With a view to provide sufficient financial assistance to such persons, the rates of old age samman allowance, widow pension and disabled pension have been increased to ₹1000 per month with effect from 1st January, 2014. Nearly 13.32 lakh persons getting old age samman allowance; 5.7 lakh widows and destitute women; and about 1.36 lakh disabled persons will be benefitted with this increase. In the year 2013-14, a new scheme named 'Indira Gandhi Priyadarshni Vivah Shagun Yojna' was launched to provide financial assistance on the occasion of marriage of the daughters of widows, orphans and destitute persons. Under these schemes financial assistance ranging from ₹10,000 to 31,000 is being given. Another scheme of Kanyadaan was started under which an amount of ₹ 11000 per marriage is provided to the NGOs for organizing mass marriages (at least 11 marriages at a time). For the welfare of the minorities in the State, government has taken a decision in principle to set up the 'State Minorities Commission'. I propose to earmark ₹ 2877.25 crore on the plan side and ₹ 33.99 crore as non-plan side in the financial year 2014-15 for the department of Social Justice and Empowerment.

Welfare of SCs & BCs

58. The Government is fully committed to the welfare of persons belonging to Scheduled Castes and Backward Classes. Several schemes are being implemented for their social, economic and educational development. For encouraging children belonging to these weaker sections to continue their education beyond matric, under the post-matric scholarship scheme, 38791 persons were given scholarship at a cost of ₹ 6347.52 lakh till 31st January, 2014

59. I propose to allocate ₹ 154.91 crore on non plan side and ₹ 213.40 crore on plan side in the financial year 2014-15 for the department of Welfare of SCs & BCs.

Women & Child Development

60. Well being of women and children has to be accorded top most priority by any developing society. No society can progress without taking due care of women and children. During pre-delivery as well as post delivery phases both mother and child require constant care and monitoring of their health and nutrition. Integrated Child Development Services (ICDS) scheme is a flagship scheme of the Government to improve health, nutritional, psychological and social developmental status of children of 0-6 years. Haryana has set up a robust network of 25,962 anganwadi centres administered through 148 ICDS projects including 21 urban projects for providing these services to the targeted persons. Six important services are provided under the scheme, namely, supplementary nutrition, immunization, health check up, referral services, non formal pre-school education and health and nutrition education of the children up to 6 years of age, pregnant and nursing mothers; and other girls/women in the age group of 15-45 years in an integrated manner.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

61. Anganwadi centres are the focal points for implementation of various schemes in this regard. New Anganwadi centres are being constructed with the help of funds provided by the State as well as loan taken from NABARD. For encouraging anganwadi workers and helpers, their honorarium has been increased significantly. Now ₹ 7500 per month will be given to anganwadi workers, ₹ 4000 per month to mini anganwadi workers and ₹3500 per month to anganwadi helpers.

62. I propose to allocate ₹ 616.65 crore in the plan including central share, and ₹ 220.31 crore on the non-plan side for the department of Women & Child Development.

16.00 बजे

Health & Medical Education

63. Good care of health is a fundamental need of the people for which purpose an extensive network of health institutions has been established in the State. In the last four and half years buildings of 6 general hospitals, 4 trauma centres, 8 community health centres (CHCs)-cum-general hospitals, 13 CHCs, 66 primary health centres (PHCs) and 193 sub health centres have been constructed with a cost of ₹321.25 crore. In addition to the above, administrative approval for the buildings of 15 general hospitals, 21 CHCs, 42 PHCs, and 91 sub health centres has been granted involving expenditure of ₹430.38 crore. The process of construction of these buildings is at different stages. A landmark programme named 'Mukhya Mantri Muft Ilaj Yojana' has been launched under which all medical treatments including free surgeries and free medicines are being provided in state government health institutions. This programme is benefitting the entire population of the State. For their better motivation remuneration of ASHA workers has been increased. This will benefit nearly 16800 ASHA workers in the state. A few years ago a decision was taken to establish 3 new medical colleges in the state sector; two of which at Khanpur Kalan, in district Sonapat and Nalhar, in district Mewat, have already become operational. Construction work of the third medical college at Karnal has commenced in full swing. New Medical Colleges are proposed to be set up in district Bhiwani and in the Central University, Mahendragarh. The medical colleges are not only treating thousands of patients every day, but they are also educating valuable manpower which will increase the availability of the doctors in the state in future.

64. I propose to allocate ₹ 1145.62 crore to health and ₹ 528.60 crore to the medical education sector on plan side in the year 2014-15. Besides, a provision of ₹ 979.94 crore and ₹ 150 crore on non-plan side respectively is proposed.

School Education

65. Education continues to be one of the top most priorities of the Government. Since 2005, 1314 schools have been upgraded from primary to middle level; 294 from middle to high; 26 from middle to senior secondary level and 611 from high to senior secondary level.

66. Large number of other incentives and quality improvement schemes are being implemented for improving the quality of education and access to the schools. Mid Day Meal programme is being implemented in all the elementary schools up to class eighth. For the welfare of mid day meal workers, monthly honorarium has been increased from ₹ 1150 to ₹ 2500 per month. I propose to earmark ₹ 5276 crore under the non plan and ₹3123.10 crore under the plan schemes, including central share, for the school education in the budget estimates 2014-15.

Higher Education

67. For greater access and improved quality of higher education, the network of colleges and universities has been vastly expanded, strengthened and upgraded in the last four years. At present there are 95 government colleges and 24 universities in the State as against 75 colleges and 6 universities in the year 2009-10. Besides, there are 97 private aided colleges in the State. There are also 12 other universities set up under the aegis of Health, Agriculture, Animal Husbandry and Technical Education Department. It is a conscious policy of the State to encourage setting up of higher education institutions in the state, private as well as aided sectors. Compulsory computer education is being provided in 95 government colleges. Construction work of National Law University, to be named after Dr. B.R. Ambedkar, in Rajiv Gandhi Education City, Kundli (Sonepat) is likely to commence soon. 32 Government colleges have been selected for developing into centres of excellence. It is also proposed to set up a Sports University at Bhiwani to be named as Chaudhary Bansi Lal Sports University. Regional Centre of Kurukshetra University at Jind is proposed to be upgraded as a University. Regional Centres of BPS Mahila University, Khanpur Kalan are proposed to be established at Lula Ahir in district Rewari and at Kanya Gurukul, Kharal, Narwana, district Jind. A Regional Centre of Mulana Azad Urdu University, Hyderabad is also proposed to be set up at Nuh district Mewat. I propose to allocate ₹ 462.12 crore on the plan and ₹ 752.42 crore on non plan side for the higher education department in the budget estimates of the year 2014-15.

Technical Education

68. The network of engineering colleges, polytechnics and ITIs, both in the public as well as private sectors has been greatly expanded and strengthened. At present there are 159 engineering colleges, 202 polytechnics and 229 ITIs in the State with a total seats capacity of 2,00,997. This capacity has been increased from 1,51,886 in the year 2009-10. Besides, several other institutions have either been set up or are in the process of being set up, including Indian Institute of Management, Rohtak; National Institute of Design, Kurukshetra; National Institute of Fashion Technology, Panchkula; Extension campus of IIT Delhi for faculty development, at Rajiv Gandhi Education City, Kundli; Extension campus of IIT Delhi for research and development at village Bhadhsa, district Jhajjar; Indian Institute of Information Technology, Sonepat, etc. For various programmes of promoting technical education in the State, I propose to earmark ₹ 104.70 crore on the non plan side and ₹ 456.50 crore on plan side for the Technical Education Department for the financial year 2014-15.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

Sports

69. Sports play a vital role in improving the quality of human resource. A good sports person is usually a good human being and attains success in all walks of life. Full spectrum of sports activities have been undertaken for promotion of sports in the State. The results of the efforts made by the Government are already evident as the sports persons from Haryana have been bringing laurels to the country in various international and national sports events.

70. The policy of providing government jobs to outstanding sports persons is being implemented earnestly under which large number of outstanding sports persons have been given Government jobs. Cash awards for the medal winners of Olympic games, 2016 have been doubled. The gold, silver and bronze medalist in these games will be given ₹ 5 crore, ₹ 3 crore and ₹ 2 crore respectively. Similarly, award money for medal winners and awardees in various other national and international events has been considerably enhanced. In 2012-13, ₹ 15 crore were disbursed as awards to 2005 outstanding players, which is likely to be of the order of ₹ 20 crore to 2050 medal winners in the year 2013-14. It has also been decided to give ₹ 5 lakh as cash award to those persons from Haryana who scale Mount-Everest.

71. Large scale sports infrastructure is being created and upgraded. A 100 bedded sports hostel at Meham district Rohtak; Basketball academy at village Kilo district Rohtak; football academy with artificial football surface at Dariyapur district Fatehabad; and astroturf hockey fields at Bhiwani, Jeevan Nagar in district Sirsa and at Hisar have been planned.

72. For identification of sports talent and for nurturing it to excel, Sports and Physical Aptitude Test (SPAT) is being conducted. It involved 12.70 lakh children in 2014 out of which 1.80 lakh were selected in the first round and eventually 5000 will be selected for award of scholarship and further training. An amount of ₹ 10 crore will be spent on their scholarship.

73. Besides, play fields are being set up at village level and are planned to be set up in all the villages of the State over a period of 10 years. World class academies are being set up by Olympic medalists of Haryana. 14 residential and 11 day boarding nurseries are also being run.

74. I propose to earmark ₹ 124.48 crore on plan side and ₹ 68.80 crore on non-plan side for encouragement of sports activities in the State in the financial year 2014-15.

Welfare of Defence Personnel

75. Our Government has always accorded due respect and honour to the serving soldiers as well as ex-servicemen of the armed forces. Significant increase has been made in the rates of cash awards, annuities and monthly allowances admissible to different categories of medal winners and gallantry award winners,

including their widows. The rates of ex-gratia grants in the unfortunate event of death during action against militants, extremists or during borders skirmishes have been considerably enhanced. As a mark of respect to the brave soldiers, the amount of cash awards paid to the Gallantry Award winners (war time) is proposed to be enhanced from ₹31 lakh to ₹ 2 crore for the awardees of Paramvir Chakra; from ₹ 21 lakh to ₹ 1 crore for the awardees of Mahavir Chakra; from ₹ 15 lakh to ₹ 50 lakh for the awardees of Vir Chakra; from ₹ 7.50 lakh to ₹ 21 lakh for awardees of Sena Medal (Gallantry) and from ₹ 5.50 lakh to ₹ 10 lakh for mention-in-dispatches (Gallantry). For peace time Gallantry Award winners the amount has been increased from 31 lakh to ₹ 1 crore for Ashok Chakra, from ₹ 21 lakh to ₹ 51 lakh for Kirti Chakra, from ₹ 15 lakh to ₹ 31 lakh for a Shourya Chakra from ₹ 7.50 lakh to ₹ 10 lakh for Sena/Nausena/Vayusena medals; and from ₹ 5.50 lakh to ₹ 7.50 lakh for mention-in-dispatches (Gallantry).

76. The Housing Board has also initiated a programme for construction of 50,000 nine storied affordable flats for the Serving and Ex-Servicemen of defence forces and Para Military Personnel. The Housing Board has already floated registration for 13,696 houses in the first phase. These flats will be made available at affordable rates on easy installments to the eligible persons. The size of the flats would be 500 Square feet and 600 Square feet. The total cost of the project would be ₹ 8250 crore to be completed in 3 years.

Food & Supplies

77. Haryana is fully geared for efficient procurement of the food grains produced by our farmers. During the Rabi marketing season 2013, 58.56 lakh MT wheat was procured for Central pool at the minimum support price of ₹1350 per quintal. Similarly during Kharif marketing season 2013, 35.75 lakh MT paddy was procured at the declared minimum support price of ₹1310 for the common varieties and ₹1345 per quintal for grade 'A' variety of leivable paddy. The storage capacity in the State is being increased significantly. Under the Private Entrepreneur Godown (PEG) Scheme, 36.52 lakh MT of godown capacity is being constructed for which HAFED has been declared as the nodal agency. Up to December, 2013, 19.33 lakh MT capacities have already been created and 11.64 MT capacities are under construction.

78. For providing remunerative prices to the farmers efficiently, an arrangement of ₹ 7350 crore has been made for the year 2014-15. It will be ensured that the payment to the farmers is made without any delay.

79. Haryana is amongst the first states in the country to launch and implement National Food Security Act, 2013 with effect from 20th August, 2013. Nearly 1.26 crore persons will be benefitted under this scheme. For improving nutritional standards of the poorer segments of society, an innovative 'Dal Roti' Scheme was also launched from 20th August, 2013, under which 2.5 Kg. of pulses at a highly subsidized price of ₹20 per Kg. per month is supplied to all the Antyodaya Anna Yojna (AAY) and other below poverty line families. A provision of ₹ 162 crore has been made for this scheme in the budget estimates of the year 2014-15.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

Cooperation

80. Requisite credit facilities are being provided to the farming community and rural masses through 656 primary agriculture cooperative societies. Up till November, 2013, ₹3327.96 crore worth of loans were disbursed by the HARCO Bank through various cooperative institutions. In order to give relief to the loanees a recovery linked incentive scheme, 2013, has been launched under which interest relief of 8 percent is being granted to the farmers on the outstanding crop loans. Besides, 50 percent interest relief is being given on medium term agriculture as well as medium term non-agriculture over-due loans which were outstanding as on 31st March, 2013. For the loanees of Haryana State Cooperative Agriculture and Rural Development Bank another recovery linked incentive scheme has been launched. Under this scheme also 50 percent remission of overdue interest will be provided by the State Government. These schemes will not only help the loanees but would also help improve recovery of the overdue outstanding loan amount. I propose an outlay of ₹ 211.77 crore on plan and ₹ 109.28 crore on non-plan side for the Cooperation for the year 2014-15.

Transport

81. Efficient transport system is an essential need of the public. For this purpose, plan outlay of the department has been increased from ₹ 181.50 crore during the current financial year to the proposed outlay of ₹ 197.40 crore for the year 2014-15.

82. Haryana Roadways is providing transportation services to around 11.57 lakh passengers every day with its fleet of about 3800 buses operating from 24 depots and 13 sub-depots. Haryana Roadways is committed to provide safe transport services to the public. With earnest efforts, the rate of accidents in Haryana Roadways has been reduced to the lowest in the country. For its efforts, Haryana Roadways has been awarded Union Transport Minister Trophy for lowest accident rate among all the state roadways transport undertakings in the country during the year 2005-06 to 2007-08, 2009-10 and 2012-13. A new scheme of road safety awareness and computerization of regulatory wing of the department has been launched. To provide comfortable transport service to the passengers on Chandigarh-Delhi-IGI-Gurgaon route, the number of Volvo/Mercedes Super Luxury A.C. buses has been increased to 45. This service has been widely appreciated by the public. Rohtak and Hisar were connected from Chandigarh with this service during the current year.

83. Haryana Roadways has also introduced City Bus Service in Faridabad city with about 100 buses. For this purpose, a separate city bus service depot has been set up in Faridabad. Similarly, Gurgaon has been provided with 120 and Panchkula with about 35 intra-city buses.

84. Haryana Roadways is providing concessional travel facility to about 37 different categories of citizens. Girl students have been allowed free travelling with effect from 01.01.2014 from the nearest bus stop of their residence to the bus

stop of educational institution up to 60 Km. Cancer patients have also been allowed free travelling from nearest bus stop of their residence to the cancer institute with effect from 1st January, 2014. 50 percent concession is proposed to be granted in ordinary buses of Haryana Roadways to all those persons who are above the age of 65 years. I propose a provision of ₹ 1872.68 crore on non plan side for the department for the year 2014-15.

Tourism

85. Haryana may not be very richly endowed with natural attractions like mountains, rivers, sea shores etc. but it has its own charm of highly developed rural areas and four main National Highways passing through it. Making full use of this endowment, Haryana Tourism has created a network of tourist complexes all over the State which are providing much needed business and tourism facilities to the travelling public. Surajkund Mela has acquired world fame. Several other festivals are organized by tourism department for promotion of tourism in the State. I propose to allocate an amount of ₹31.50 crore on plan side for promotion of tourism in the financial year 2014-15.

Treasuries & Accounts

86. At present there are 21 district level treasuries and 85 sub treasuries in the state which maintain the accounts of all receipts and payments relating to the consolidated fund of the State and public accounts of the State. The treasuries department has made a remarkable achievement by developing an Integrated Financial Management System for the State Government. This project has been envisaged to make budgetary controls more effective; improve cash flow management; promote day-to-day reconciliation of accounts; improve accuracy and timeliness in preparation of accounts, and to bring about transparency and efficiency in public delivery systems and improved quality of governance in the State. Through this system the processes of generation and submission of pay bills, pension management, loans and re-imbursements to employees have been completely integrated and are being performed with minimum manual intervention.

87. As a part of the project e-Billing system has been made fully operational all over the State with effect from 1st April, 2013. All types of bills are being prepared and submitted in the treasuries by the DDOs through this system. The existing e-Salary system has been fully integrated with this system. Web enabled on-line treasury information system has also been implemented in all treasuries and sub-treasuries in the current financial year. With this system all the activities related to expenditure in the treasuries have been computerized. Electronic Government Receipt Accounting System (e-GRAS) was also implemented with effect from November, 2013. Under this system on-line facility for generation of challans for depositing money is available. This system has not only facilitated convenience of the payers but also made the accounting and reconciliation process much easier and accurate. For the facility of pensioners, e-Pension system has been implemented and now the pension of the pensioners is being credited in their accounts through this system. The on-line budget allocation, monitoring and analysis system is also being implemented very effectively.

[Sardar Harmohinder Singh Chattha]

88. I propose to allocate ₹ 62.78 crore to the Treasuries & Accounts and Local Audit departments in the year 2014-15.

Mines and Geology

89. Mining activity had come to a standstill on account of various legal disputes in the courts. After vigorously pursuing the cases, the state could get the main issue finally settled in October 2013. The department has successfully auctioned 42 of its minor mineral mines during the month of December 2013 fetching the state an annual bid amount of ₹ 2133.93 crore for 42 mining Units in the state, which is unprecedented. However, actual commencement of the mining activities may take some time due to the requirement of environmental clearances.

Electronics & Information Technology

90. The State has taken a number of initiatives for delivery of citizen services in electronic mode. More than 100 citizen services have been identified across various government departments and organizations which are envisaged to be delivered in electronic mode using the information and communication technology. The Department of Information Technology has developed an application known as the "Integrated Village Information and Services System" (IVISS) for delivery of citizen services in a hassle-free manner across the state through a network of Common Service Centres (CSCs), planned to be established as a convergence business model operated through a Village/Urban Level entrepreneur. It is proposed to implement the e-district project using the IVISS platform, and services will be delivered through the e-Disha Centres and the CSCs. Several Individual departmental services are proposed to be integrated with IVISS in an incremental manner and delivered through the CSCs.

91. Recognizing that reliable connectivity with adequate bandwidth is a prerequisite for effective adoption and use of Information Technology, the Government of India has decided to provide last mile connectivity under its national optical fibre network project. The State has also signed a MoU in this behalf.

92. In addition to the above, steps have been taken for implementation of a number of mission mode and other major e-governance projects. These include computerization of commercial taxes of excise and taxation department, hospital information management system of the Health department, APDRP of the Power department, and integrated financial management systems of the Finance Department, apart from the ongoing projects of Transport, Revenue, Panchayats, and Treasuries, which are at different stages of implementation.

Excise & Taxation

93. Speaker Sir and Hon'ble Members, I am happy to announce that the budget for the year 2014-15 is a tax free budget. Not only that, during the current financial year our Government has reduced the taxes on several goods. VAT on goods sold through CSD canteens to serving defence personnel and ex-servicemen were reduced from 5% to 4%. Similar concession has been granted to the personnel of

central para military forces also. For facilitating convenience of students' non-AC private buses dedicated for the students have been exempted from the payment of passenger tax. For the facilities of industry and trading community, VAT D-3 Form has been abolished w.e.f. 1st January, 2014. The limit for issuing cash memo by registered dealer has been raised from ₹ 300 to ₹ 1000.

Budget Estimates 2014-15

94. Sir, under the budget estimates 2014-15, total receipts (net of public debt) are projected at ₹ 59173.10 crore, of which revenue receipts are ₹ 47690.14 crore and capital receipts (net of public debt) are ₹ 11482.96 crore. These receipts have registered an increase of ₹ 7523.32 crore representing an increase of 14.57%; ₹ 6054.20 crore showing increase of 14.54%; and ₹ 1469.12 crore showing increase of 14.67%; respectively over the corresponding projections in the revised estimates of 2013-14. The total expenditure (excluding the repayments) under the budget estimates for the year 2014-15 is projected at ₹ 59451.23 crore, of which revenue expenditure is ₹ 52702.71 crore and the capital expenditure is ₹ 6748.52 crore. These categories have marked an increase of ₹ 5902.93 crore representing increase of 11.02%; ₹ 5453.85 crore showing increase of 11.54%; and ₹ 449.08 crore showing increase of 7.13%; respectively over the corresponding projections in the revised estimates of 2013-14.

95. Sir, let me now indicate the sectoral allocations in the budget estimates for the year 2014-15. Agriculture and Allied sectors would receive ₹ 2156.31 crore; Power sector is proposed to receive ₹ 5360.14 crore, Road and Transport sector has been allocated ₹ 4987.80 crore; Irrigation sector is projected to receive ₹ 2209.75 crore; Public Health Engineering sector is slated to receive ₹ 2427.99 crore; Urban Development sector has been allocated ₹ 3006.71 crore; Education, Sports, Art & Culture sector is slated to receive ₹ 9819.67 crore; Industrial Training and Technical Education are projected to receive ₹ 880.81 crore; Health and Family Welfare sector is allotted ₹ 2804.41 crore; Social Justice and Empowerment including Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes sector is proposed ₹ 4418.30 crore; and Rural Development and Panchayat sector is slated to receive ₹ 2310.37 crore.

Sir, with these words, I now commend the Budget Estimates for the year 2014-15 to this house for its consideration and approval.

Jai Hind !

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, the House is adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 3rd March, 2014.

***16.36 hrs.** (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 3rd March, 2014.)

